WWW.Kanchanujala.in
हिन्दी दैनिक
kanchanujala14@gmail.com

कंचन उजाला

जैकलीन ने लीडिंग मैगजीन के कवर पर बिखेरा जादू

लखनऊ से प्रकाशित
सच्चाई के साथ

वर्षः 01 अंक : 271 | लखनऊ, रविवार, 20 सितम्बर, 2020 | पृष्ठ- 6 | मूल्य - 1 रुपये

बंगाल-केरल से अल-कायदा के 9 आतंकी गिरफ्तार

➲ देश में कई स्थानों पर थी हमले की साजिश

नई दिल्ली एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम से अल-कायदा के 9 आतंकियों को गिरफ्तार कर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसी को पश्चिम बंगाल और केरल सहित देश में विभिन्न स्थानों पर अल-कायदा के अंतर-राज्य मॉड्यूल के बारे में सूचना मिली थी। कथित तौर इन मॉड्यूल में देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमले करने की योजना बनायी जा रही थी। अधिकारी ने कहा कि इसके बाद एनआईए ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। उन्होंने का कि शनिवार को मारे गए छापे इसी कार्रवाई का हिस्सा हैं। अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में पश्चिम बंगाल से 6 और केरल से 3 आतंकी शामिल हैं। मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार 6 आतंकियों में अबु सुफियान, मैनुल मोंडल, लेउ यीन अहमद, अल मामुन कमाल और

अतीतुर रहमान हैं। केरल से काबू किए आतंकियों में मुर्शीद हसन, इयाकुब विश्वास और मोसराफ हुसैन हैं। अधिकारी ने कहा कि यह आतंकी मॉड्यूल सक्रिय रूप से धन उगाही में लगा हुआ था और गिरोह के कुछ सदस्य हथियारों और गोला-बारूद की खरीद की योजना बना रहे थे। इनकी गिरफ्तारी से देश के विभिन्न हिस्सों में संभावित आतंकवादी हमलों की पूर्व सूचना मिली है। एनआईए ने बताया कि इनके पास से बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, धारदार हथियार, स्वदेशी आग्नेयास्त्र, एक स्थानीय रूप से निर्मित शरीर कवच, घर में विस्फोटक तैयार करने से संबंधित लेख और साहित्य जब्त किए गए हैं। एनआईए ने गिरफ्तार 9 आतंकवादियों में से कुछ की फोटो जारी की है। एनआईए ने बताया कि लियू यीन अहमद और अबू सुफियान को पश्चिम बंगाल से तथा मोशर्रफ हुसैन और मुर्शीद हसन को केरल से गिरफ्तार किया गया है।

एक हफ्ते में होगी 31661 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्तीः योगी

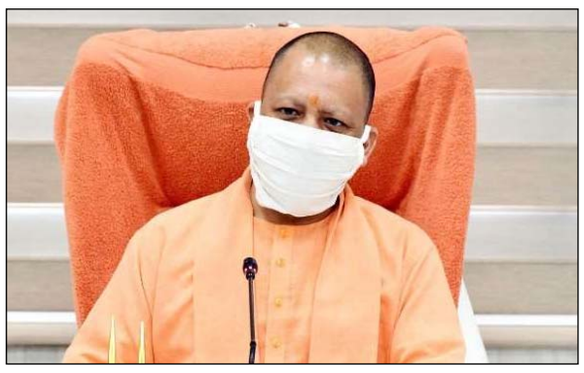

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। सरकार 31661 पदों पर एक हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 31661 पदों पर भर्ती की छूट दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब उन्हीं 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरी करेगी। इसके बाद के बचे पदों पर भर्ती सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद ही होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापकों के

69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 06 जनवरी, 2019 को टीटीई की परीक्षा कराई गई थी। 07 जनवरी, 2019 को निर्गत शासनादेश से टीटीई परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया था। शासनादेश के सम्बन्ध में कतिपय अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में रिट याचिकाएं योजित की थी।मुख्य रिट याचिका रामशरण मौर्या बनाम राज्य सरकार व अन्य में हाई कोर्ट ने 29 मार्च, 2020 को शासन के पक्ष में निर्णय दिया गया। विशेष अनुज्ञा याचिका सं-11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में सुप्रीम कोर्ट के 21 मई, 2020 को पारित आदेश में राज्य सरकार को यह निर्देश दिए गए कि शिक्षामित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। अतः अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूर्ण कर लें।

योगी सरकार ने तीन साल में ही सपा-बसपा से दी अधिक नौकरियां

लखनऊ, एजेंसी। यूपी में सरकारी नौकरियों के पिछले 13 सालों के आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो प्रदेश की मौजूदा सरकार ने सपा और बसपा सरकारों से कहीं अधिक नौकरियां दी हैं। बसपा सरकार ने पांच साल में 91000 और सपा सरकार ने पांच साल में 2.5 लाख नौकरियां दी हैं। कार्मिक विभाग के आंकड़ों को देखा जाए तो योगी सरकार में अब तक 294080 नौकरियां दी गई हैं। इसका औसत निकाल जाए तो हर साल एक लाख युवाओं को नौकरियां दी गई। मौजूदा समय 85629 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसे मिला दिया जाए तो यह संख्या 379709 हो जाती है। प्रवक्ता के मुताबिक राज्य सरकार ने लोकसेवा आयोग की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का काम किया। विश्वसनीयता, पारदर्शिता और इंटीग्रिटी पुनः स्थापित हुई। अध्यक्ष पद पर ईमानदार व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई। परिणाम यह रहा है कि आयोग ने मात्र तीन सालों में ही 26103 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया। पिछली सरकार में पांच सालों में 26000 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ था। भाजपा सरकार में हुए चयन में 141 उपजिलाधिकारी, 184 पुलिस उपाधीक्षक, डॉक्टरों में एलोपैथिक 4108, होम्योपैथिक 773, आयुर्वेदिक 969 और डेंटल सर्जन 535 रखे गए। इसके साथ ही पीसीएस जे के पदों पर 610 का चयन हुआ।नियुक्तियों में जहां रिकार्ड टूटा, वहीं अफसरों को पदोन्नति देने में भी पिछड़ी सरकारों को पीछे छोड़ा गया। लोकसेवा आयोग के आंकड़ों के मुताबिक तीन सालों में 6566 अफसरों को पदोन्नतियां दी गई हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल में मात्र 1588 अधिकारियों को ही पदोन्नतियां मिली थीं।

समय पूर्व खत्म हो सकता है सत्र

नयी दिल्ली एजेंसी। सरकार सांसदों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर मौजूदा मानसून सत्र को निर्धारित समय से पहले खत्म करने पर विचार कर रही है, हालांकि इस बारे में कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में विभिन्न दलों के नेता आज बैठक कर इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकार सभी दलों को विश्वास में लेने के अलावा 11 अध्यादेशों को विधेयक के तौर पर पारित करा लेना चाहती है। लोकसभा ने कृषि से संबंधित तीन विधेयकों को पारित कर दिया है। ये विधेयक अध्यादेशों के स्थान पर लाए गए थे। इसके साथ सांसदों के वेतन में कटौती से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाए गए विधेयक को भी सदन की मंजूरी मिल गई है।सूत्रों ने कहा कि सत्र के दौरान संसद के कुछ सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। विपक्षी दलों ने सरकार से कहा है कि 18 दिनों का सत्र जोखिम भरा हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस दिशा में विचार करना आरंभ कर दिया है। गत 14 सितंबर से सत्र की शुरुआत होने के बाद से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रह्लाद पटेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।

नई शिक्षा नीति देश को नये परिवेश में बदलेगीः रामनाथ कोविंद

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार की गयी है जो अभूतपूर्व और पूर्ण व्यवस्थित है और यह देश को नया परिवेश प्रदान करेगी। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उच्च शिक्षा में कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए आयोजित किये गए कुलाध्यक्ष सम्मलेन (विज़िटर्स कांफ्रेंस) को संबोधित करते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में शामिल होते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों का नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में बहुत बड़ा योगदान है। नई शिक्षा नीति देश को नए परिवेश में परिवर्तित करेगी। उन्होंने डॉ के कस्तूरीरंगन की सराहना करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार की गयी है जो अभूतपूर्व और पूर्ण व्यवस्थित है।

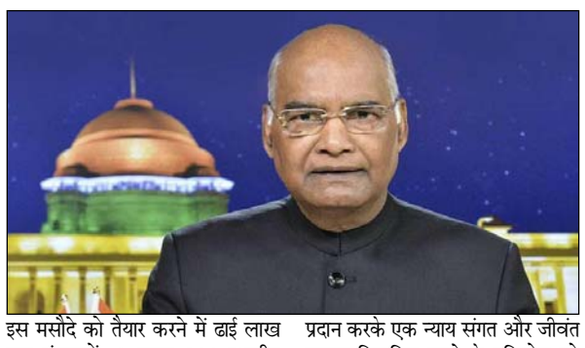

इस मसौदे को तैयार करने में ढाई लाख ग्राम पंचायतों,12 हजार 500 स्थानीय निकायों और 675 जिलों के लोगों से परामर्श लिया गया है। इस नीति को बनाने में करीब दो लाख लोगों से परामर्श लिया गया है। कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 21 वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हमारी शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके एक न्याय संगत और जीवंत समाज विकसित करने के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। यह समावेश और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा व्यवस्था की पिरामिड में सबसे ऊपर रहने के लिए आज के दौर में उच्च शिक्षा संस्थानों की महत्ता और उत्तरदायित्व सर्वाधिक है तभी हम भारत के 'सुपर पावर' बनने की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे।

पार्क रोड पर राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन मे कराए गए नुक्कड नाटक का पराश्रिमक न मिलने पर रोड के किनारे नाटक प्रदर्षन करते कलाकार

कोरोना महामारी के कारण लाना पड़ा अध्यादेशः सीतारमण

नई दिल्ली, वार्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को राज्यसभा में कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुयी अभूतपूर्व स्थिति के कारण लाया गया था। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण बनी स्थिति की वजह से समय की मांग थी कि तत्काल कदम उठाए जाएं और उसके लिए अध्यादेश का तरीका चुना गया। वित्त मंत्री ने कहा कि अध्यादेश को कानून बनाने के लिए सरकार अगले ही सत्र में विधेयक लेकर आ गयी। वह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन), 2020 पर हुयी चर्चा का जवाब दे रही थीं। उनके जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही सदन ने माकपा सदस्य केके रागेश द्वारा पेश उस संकल्प को नामंजूर कर दिया जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को अस्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया था।

नमो कंचन सेवा समिति माध्यम से गरीब को हर संभव मदद देने की भरपूर कोशिश की

रुद्र प्रताप सिंह, रिपोर्ट, लखनऊ। लॉकडाउन के बेहद मुश्किल दिनों में नमोकंचन सेवा समिति ने जरूरतमंद असहाय लोगों को पूरे लॉकडाउन के महीनों तक खाद्य सामग्री आवश्यक वस्तुएं बांटी गयी लखनऊ नमो कंचन सेवा समिति माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को हर संभव मदद देने की भरपूर कोशिश की गई लॉकडाउन में भी लगातार हर जरूरतमंद लोगों को निरंतर सेवा भाव का प्रयास जारी रखा जन जन तक हर सुविधा मुहैया कराने की पुरजोर कोशिश रही राजधानी लखनऊ में

नमोकंचन सेवा समिति ने इम्युनिटी बूस्टर और चॉकलेट के बांटे पैकेट

लखनऊ। नमोकंचन सेवा समिति ने शनिवार को हुसैनगंज स्थित बच्चों को इम्युनिटी बूस्टर और चॉकलेट के पैकेट का वितरण किया। समिति की अध्यक्ष कंचन सोलंकी की मौजूदगी में समाजसेविका सैय्यद ज़रीन और सतीश कुमार चतुर्वेदी ने वहां मौजूद लोगों को राहत सामग्री के पैकेट बांटे। बता दे कि लॉक डाउन के बेहद मुश्किल दिनों में नमोकंचन सेवा समिति ने असहाय लोगों को कई महीनों तक खाद्य सामग्री बांटी थी।

समाज सेविका द्वारा इससे पूर्व में करोना वायरस की लड़ाई में किया गए अति सराहनीय पहल कोरोना वायरस के हालात को देखते हुआ कोरोना वायरस के बचाव के लिये सैनिटाइजर व मास्क वितरण किया गया जिससे ग्रामीण लोग कुछ राहत की साँस ले सके सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि घर पर ही रहें और घरों से बाहर जब निकले जब कोई आवश्यक कार्य हो और मास्क लगाकर घर से बाहर निकले खुद बचे और दूसरों को बचाएं और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कोरोना से फैली महामारी से बचाव के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है लेकिन कुछ लोग मनमर्जी कर रहे हैं जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ सकता है।

आखिरी सफर पर निकला आईएनएस विराट

मुंबई, एजेंसी। भारतीय नौसेना का सेवामुक्त विमानवाहक युद्धपोत विराट शनिवार को अपनी अंतिम समुद्री यात्रा पर गुजरात स्थित अलंग के लिए रवाना हुआ जहां उसे विघटित करने के बाद कबाड़ के रूप में बेच दिया जाएगा। विशालकाय युद्धपोत विराट को पूर्व नौसैनिकों ने गेटवे ऑफ इंडिया से भावभीनी विदाई दी। मार्च 2017 में सेवामुक्त किए जाने के बाद नौसेना डॉकयार्ड से विराट की अंतिम यात्रा की शुरुआत हो गई थी। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि विराट को शुक्रवार को ही जाना था लेकिन कुछ कारणों से एक दिन का विलंब हुआ। विराट ने भारतीय नौसेना में 30 वर्षों तक सेवा दी थी। मूल रूप से यह ब्रिटेन की रॉयल नेवी में एचएमएस हरमेस नामक युद्धपोत था और भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के बाद इसका नाम भारतीय नौसैनिक पोत (आईएनएस) विराट रखा गया था। विराट को संग्रहालय बनाने का प्रयास किया गया था।

➲ अजीत डोभाल ने किया अलर्ट

साइबर क्राइम में 500 फीसदी तेजी

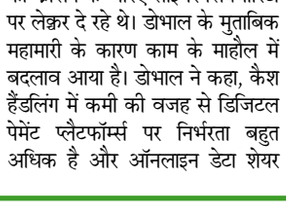

मुंबई, एजेंसी। ऑनलाइन होते समय सावधानी बरतने की अपील करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 में के बाद डिजिटल पेमेंट प्लैटफॉर्म्स पर बहुत अधिक निर्भरता होने की वजह से वित्तीय धोखाधड़ी में बहुत वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार नेशनल साइबर सिक्यॉरिटी स्ट्रैटजी-2020 लेकर आ रही है, जो भारत की समृद्धि के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय, लचीला और जीवंत साइबर स्पेस मुहैया कराएगा। अजीत डोभाल केरल पुलिस और सोसायटी फॉर द पुलिसिंग ऑफ साइबर स्पेस एंड इन्फॉर्मेशन सिक्यॉरिटी रिसर्च असोसिएशन की ओर से आयोजित डेटा प्राइवेसी और हैकिंग कॉन्फ्रेंस

COCONXIII-2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साइबर सिक्यॉरिटी पर लेक्चर दे रहे थे। डोभाल के मुताबिक महामारी के कारण काम के माहौल में बदलाव आया है। डोभाल ने कहा, कैश हैंडलिंग में कमी की वजह से डिजिटल पेमेंट प्लैटफॉर्म्स पर निर्भरता बहुत अधिक है और ऑनलाइन डेटा शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया की मौजूदगी भी बढ़ गई है। जबकि हम एक हद तक अपने मामलों को ऑनलाइन मैनेज करने में सक्षम हैं, बुरे इरादे वाले इसमें एक नया अवसर पाते हैं। डोभाल ने कहा कि सीमित जागरूकता और साइबर स्वच्छता की वजह से साइबर अपराध में 500 फीसदी की तेजी आई है। डोभाल ने कहा, डिजिटल पेमेंट प्लैटफॉर्म्स पर अधिक निर्भरता की वजह से वित्तीय धोखाधड़ी में घातीय वृद्धि हुई है। दुश्मन आपदा की इस घड़ी का गलत सूचनाओं, फर्जी समाचार से फायदा उठाना चाहते हैं। साइबर स्पेस में तैरता विशाल साइबर डेटा सोने की खान की तरह है जिससे जानकारी निकालने से हमारे नागरिकों की निजता में सेंध लगाई जा सकती है।

देश में कोरोना के 93,337 नये मामले

➲ देश में करीब 95,880 लोग कोरोन वायरस से हुए स्वस्थ

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में दो दिन तक वृद्धि के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान नये मामलों में कुछ कमी आई है और 93,337 नये मामले सामने आये जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 53 लाख के पार हो गया, जबकि राहत की बात यह है कि इस दौरान रिकॉर्ड 95,880 लोगों के स्वस्थ होने से इससे निजात पाने वालों की संख्या 42 लाख से अधिक हो गयी। इसके साथ ही भारत कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ पहले नंबर पर आ गया है। दुनिया के सभी देशों की तुलना में भारत में कोरोना के सर्वाधिक मरीज

ठीक हुए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 93,337 नये मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 53,08,014 हो गया है। इससे पहले शुक्रवार को 96,424 नये मामले सामने आये थे जबकि उससे पहले गुरुवार को रिकॉर्ड 97,894 नये मामले सामने आये थे। इस अवधि में रिकॉर्ड 95 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ स्वस्थ हुए हैं जिससे कोरोना से मुक्ति पाने वालों की संख्या 42,08,431 हो गयी है। इस दौरान 1247 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 85,619 हो गयी है। नये मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक होने से सक्रिय मामले 3790 घटकर 10,13,964 हो गये हैं। देश में सक्रिय मामले 19.10 प्रतिशत और रोगमुक्त होने वालों की दर 79.28 फीसदी है, जबकि मृत्यु दर 1.61 फीसदी है। कोविड-19 से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है और यह 862 घटकर 3,01,273 हो गयी तथा 440 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 31,791 हो गया।

देश-विदेश समाचार

ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के निधन पर शोक जताया

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रुथ जिंसबर्ग के निधन पर शोक जताया है। ट्रम्प ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि जिंसबर्ग के निधन से वह दुखी हैं। उन्होंने कहा , वह एक अद्भुत महिला थीं। राष्ट्रपति ने शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए किसी भी उम्मीदवार की फिलहाल घोषणा नहीं की है। व्हाइट हाउस की प्रेस प्रवक्ता के मैक्लेनी ने कहा कि जिंसबर्ग के सम्मान में व्हाइट हाउस का झंडा झुका दिया गया है। जिंसबर्ग का शुक्रवार को निधान हो गया।वह 87 वर्ष की थी और कैंसर से जंग लड़ रही थीं। वह 27 वर्ष तक इस पद पर रहीं। एबीसी न्यूज के अनुसार इस पद के संभावित उम्मदवारों की सूची में केवल एक महिला का नाम शामिल है। सीनेट ने नेता एम मैक्कोनेल ने कहा कि ट्रम्प जिस उम्मीदवार की घोषणा करेंगे उसे चेम्बर का पूर्ण समर्थन मिलना चाहिए। जिंसबर्ग नेअपनी मौत से कुछ समय पहले अपनी पोती से कहा था कि वह चाहती हैं कि देश में राष्ट्रपति चुनाव होने तक उनकी सीट खाली रहे। सांसद चुक चुमर ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव होने तक न्यायाधीश का पद खाली रहना चाहिए।

अब बिना लक्षण वालों को भी कराना होगा कोरोना परीक्षण

ट्यूनीश, वार्ता अमेरिका की ट्रंप सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब अमेरिका में बिना लक्षणों वाले लोगों को भी कोरोना टैस्ट कराना पड़ेगा। बता दें कि पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रही है। वहीं अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने कोविड-19 परीक्षण को लेकर के दिशानिर्देशों को बदल दिया है। प्रशासन ने ऐसा दूसरी बार किया है। अब उन लोगों को भी परीक्षण कराना अनिवार्य होगा जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, बेशक उनमें किसी तरह के लक्षण न दिखाई दे रहे हों। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने अगस्त के अंत में राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों और विशेषज्ञों को उस समय नाराज कर दिया था जब यह कहा गया था कि जिन लोगों में लक्षण नहीं हैं, उन्हें परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। 24 अगस्त से पहले, सीडीसी ने उन सभी के लिए परीक्षण अनिवार्य किया था जिनमें वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे थे।

प्रियंका ने योगी को लिखा पत्र युवा बहुत हताश और परेशान हैं

पत्र में लिखा है कि बेरोजगार युवा कोर्ट, कचेहरी के चक्कर लगाने को हैं मजबूर

दिल्ली/लखनऊ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि प्रतिभावान 24 जनपदों के युवा परीक्षा पास करने के बाद भी तीन वर्षों से नियुक्ति न मिल पाने से बहुत हताश और परेशान हैं। कांग्रेस महासचिव ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि आज वह उ0प्र0 के बेरोजगार युवाओं, जो कुछ समय से पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हैं, की समस्याओं के विषय में पत्र लिख रही हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी ने पत्र में आगे लिखा है कि उ0प्र0 का युवा बहुत परेशान और हताश है। कुछ

दिनों पहले ही मैंने 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग पर बातचीत की थी। शिक्षक भर्ती में प्रदेश में 24 जिले शून्य घोषित थे यानि इन 24 जिलों में कोई जगह नहीं खाली थी किन्तु इन जिलों के बच्चे अन्य जिलों में रिक्त भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते थे और इन बच्चों ने अन्य जिलों में रिक्त भर्ती के लिए परीक्षा दी और अच्छे अंकों से पास भी हुए लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी इन युवाओं की नियुक्ति नहीं हो पायी है। उन्होने पत्र में कहा है कि युवा मजबूरी में कोर्ट और कचेहरी के चक्कर काट रहे हैं। इनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है इनका दुःख-दर्द सुनकर बहुत कष्ट हुआ है। सरकार ने इनके प्रति आक्रमक और निर्मम रवैया क्यों अपनाया हुआ है यह समझ से परे हैं। सच्चाई तो यह है कि यही उ0प्र0 का भविष्य बनाने वाली पीढ़ी है और सरकार इनके प्रति जवाबदेह है। एक तरफ नौकरी नहीं मिल पा रही है दूसरी तरफ कोरोना महामारी के कारण इनके आर्थिक कष्ट और भी बढ़ गये हैं जिसके चलते कई अभ्यर्थी अवसाद में हैं। अंत में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि मानवीय संवदेनाओं को देखते हुए युवाओं के रोजगार के हक का सम्मान करते हुए 24 शून्य जनपद के अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति कराने का कष्ट करें।

हर पार्टी तय करे कि वह किसानों के साथ है या भाजपा के साथ : चिदंबरम

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कृषि संबंधी विधेयकों के खिलाफ सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील करते हुए शनिवार को कहा कि हर पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह किसानों के साथ है या फिर %कृषकों की जीविका को खतरे में डाल रही भाजपा के साथ है। उन्होंने यह दावा भी किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़े कांग्रेस के घोषणापत्र में किसानों से किए वादों को भाजपा तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है, जबकि इस सरकार ने कॉरपोरेट के समक्ष समर्पण कर दिया है। पूर्व वित्त मंत्री ने एक बयान में कहा कि भाजपा अपने खुद के बनाए हुए जाल में फंस गई है। दशकों तक यह व्यापारियों के वर्चस्व वाली पार्टी रही और अब भी है। वस्तुओं और सेवाओं के अभाव वाली अर्थव्यवस्था का इनके द्वारा दोहन किया गया। इंदिरा गांधी द्वारा हरित क्रांति लाने और पीवी नरसिंह राव एवं मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए उदारीकरण के बाद हालात बदलने लगे। चिदंबरम के मुताबिक, आज हमारे यहां गेहूं और चावल जैसी उपज अधिक मात्रा में पैदा हो रही हैं। किसानों की ताकत की बुनियाद पर कांग्रेस की सरकारों ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई, जिसके बाद 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून बना। हमारी खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तीन स्तंभ- न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, %कांग्रेस ने 2019 में इन्हीं बुनियादी सिद्धांत के आधार पर घोषणापत्र तैयार किया था। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रवक्ता ने कांग्रेस के घोषणापत्र को जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, %हमने वादा किया था कि कृषि उत्पादक कंपनियों/संगठनों को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे किसानों की लागत, प्रौद्योगिकी और बाजार तक पहुंच हो सके।

ताइवान-अमेरिका से भिड़ने को तैयार चीन

दूसरे दिन भेजे बॉम्बर सहित 19 लड़ाकू विमान

बीजिंग, एजेंसी। चीन ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन ताइवान की तरफ और भी लड़ाकू विमान भेजे। चीन ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब ताइवान के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और एक उच्च स्तरीय अमेरिकी दूत ताइवान को लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब्दील करने वाले पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमेरिका की विदेश उप मंत्री किथ क्राच कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति पर चीन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को चीन ने दो बमवर्षक विमान सहित 19 लड़ाकू विमानों को भेजा। इससे पहले शुक्रवार को शुक्रवार को उसने 18 लड़ाकू विमानों को भेजा।मंत्रालय ने कहा कि ताइवान की वायुसेना ने इसका मुकाबला किया और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की तैनाती की गई है। गौरतलब है कि ली को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शनिवार को ताइपे स्थित एलेथिया विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें राष्ट्रपति त्साई इंग वेन भी शामिल हुईं। गौरतलब है कि ली ने ताइवान में शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित किया और चीनी मुख्यभूमि से अलग ताइवान की राजनीतिक पहचान स्थापित की। चीन, ताइवान को अलग हुआ प्रांत मानता है और जरूरत पड़ने पर ताकत के बल पर हासिल करने की बात करता है। ली का 30 जुलाई को 97 साल की उम्र में निधन हो गया था।

लखनऊ में चेरी टमाटर की बढती मांग चेरी टमाटर में लोगो की दिलचस्पी

कंचन उजाला/लखनऊ। कुछ साल पहले लखनऊ में चेरी टमाटर सितारा होटलों तक ही सीमित था परन्तु समय के साथ स्थानीय किसानों में इसकी खेती के लिए रुचि बढ़ रही है। चेरी टमाटर के कई फायदे हैं और निकट भविष्य में यह लखनऊ के पॉलीहाउस सब्जी उत्पादकों और गृह वाटिका में एक आम फसल बन जायेगा।

चेरी टमाटर समान्य टमाटर से छोटे और आकार गोल में होने के कारण चेरी जैसे दीखते हैं । कुरकुरे और खट्टे मीठे स्वाद, गूदे में कम पानी के कारण और कच्चे खाने के लिए आम टमाटर से बेहतर विकल्प है। कुरकुरे लेकिन छोटे आकार और दृढ़ता के कारण कई व्यंजनों के लिए विशेष तौर से इनका उपयोग हो रहा हैं।

पोषक तत्वों से भरपूर चेरी टमाटर मुख्य रूप से एंटीऑक्सिडेंट से खासकर विटामिन सी और लाइकोपीन के धनी हैं । इसके एंटीऑक्सिडेंट शरीर में फ्री रेडिकलस के साथ मिलकर कैंसर को रोकने में मदद करते हैं। इसके बायोएक्टिव यौगिक इसे हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। अधिक लाइकोपीन ने इसे जापान में लोकप्रिय बना दिया है क्योंकि शोधों ने उन्हें बृहदान्त्र के कैंसर को कम करने के लिए कारागार पाया है। लाइकोपीन प्रोस्टेट कैंसर को भी रोकने के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। इन छोटे टमाटरों से स्वास्थ्य लाभ आम टमाटरों से कहीं अधिक है। अधिकतर यूरोपीय देशों से चेरी टमाटर के बीज आयात किया जा रहा हैं भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने स्वदेशी किस्मों का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है । निकट भविष्य में भारत में उत्पादित बीज कम दरों पर आसानी से उपलब्ध होगा। केन्द्रीय बागवानी उपोष्ण संस्थान- के निदेशक डा.शैलेन्द्र राजन के अनुसार पिछले कई वर्षों से चेरी टमाटर की किस्मों का परीक्षण कर रहा है, जो उपयुक्त किस्म की पहचान करने और उत्पादन के तरीके को विकसित करने के लिए आवशयक है। कई ग्रीनहाउस उत्पादकों को इसकी खेती का प्रदर्शन मार्गदर्शन भी दियागया है। फलों के गुच्छों से लदी बेलें पौधों को सजावटी रूप देती हैं। संस्थान में लाल और पीले फलों से लदी बेलों को देखा जा सकता है।

ब्रिटेन में कोरोना का दूसरा वेव,नहीं होगा बड़ा लॉकडाउन

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देश में कोविड -19 महामारी का दूसरा वेव शुरु हो गया है लेकिन बड़े पैमाने पर लॉकडाउन नहीं करके सोशल डेस्टेंसिंग तथा अन्य सुरक्षा उपायों को कठोर किया जायेगा। जॉनसन ने कहा, देश में कोरोना का दूसरा वेव शुरु हो गया है। इसे रोका नहीं जा सकता था लेकिन हम राष्ट्रीय लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। इस महामारी से निबटने के लिए सुरक्षा कदमों को और कठोर किया जायेगा तथा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कर्फ्यू लगाया जायेगा। बीबीसी के अनुसार देश में राष्ट्रीय लॉकडाउन की नौबत नहीं आये इसके लिए सरकार कई कदमों पर विचार कर रही है। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए त्रिस्तरीय प्रतिबंध के उपायों पर विचार किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे को और बढ़ाया जायेगा। अस्पतालों के पास कर्फ्यू लगाया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लोग एक जगह एकत्र होकर बैठक आदि नहीं करें और ना ही आपस में मिलें। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा कि कोरोना का प्रसार तेज हुआ है और राजधानी के 90 लाख लोगों को पूर्वोत्तर लंदन की तरह कड़े सुरक्षा प्रबंधों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग के लिए राजधानी में अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाये जायेंगे।

एमपी-बीएसएफ से आए अफसरों के चलते राज्य के 6 अफसरों का आईपीएस अवार्ड अटका

रायपुर, एजेंसी। राज्य प्रशासनिक सेवा 1998 बैच के अफसरों का आईपीएस अवार्ड फिलहाल विवादों के घेरे में आ गया है। वरिष्ठ अफसरों की नाराजगी व छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस ऑफि सर्स एसोसिएशन की आपत्ति के बाद यह मामला अटग गया है। सूत्रों की माने तो यह मामला पेचीदा इसीलिए भी हो रहा है कि क्योंकि अवार्ड में एमपी और बीएसएफ से राज्य पुलिस सेवा में शामिल दो अफसरों का नाम भी शामिल है। इसके चलते जिन 6 स्थानीय अधिकारियों को अवार्ड मिलना था उनमें से अब केवल 4 लोगों का नाम ही शामिल हो पाएगा। नया विवाद राज्य सेवा से आईपीएस अवार्ड से जुड़ा है। ज्ञात हो कि राज्य सेवा वर्ष 1998 बैच के 6 अफ सरों को आईपीएस अवार्ड होना है, इसमें पहला नंबर धर्मेंद्र सिंह छवई का है, दूसरा दर्शन सिंह मरावी और तीसरा यशपाल सिंह का नाम है। इसके बाद उमेश चौधरी, मनोज खिलारी और रवि कुरे हैं। छवई मध्यप्रदेश पीएससी से 1996 में डीएसपी सलेक्ट हुए थे, छत्तीसगढ़ बनने के बाद उन्हें यहां भेजा गया, जिसके विरोध में वे हाईकोर्ट गए थे, अब वे छत्तीसगढ़ आ गए हैं। उनके आने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि मध्यप्रदेश में कि लहाल 1995 बैच के अधिकारियों को ही आईपीएस अवार्ड नहीं हुआ है. जबकि यहां 1998 बैच के तीन अफ सर राजेश अग्रवाल, विजय अग्रवाल और रामकृष्ण साहू आईपीएस हो गए हैं। इन सबके कारण सीडी टंडन, सुरजनराम भगत और प्रफुल्ल ठाकुर आदि पीछे रह जाएंगे।

वायु सेना में 10 महिलाएं उड़ा रहीं लड़ाकू विमान

नईदिल्ली , एजेंसी। भारतीय वायुसेना (आईएएफ) में सेवारत महिला अधिकारियों की कुल संख्या 1875 है और इनमें से 10 लड़ाकू विमान चालक हैं, जबकि 18 महिला अधिकारी दिशा-संचालक (नैवीगेटर) हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन के बाद भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2016 में %फ्लाइंग ब्रांच की लड़ाकू स्ट्रीम में महिला एसएससी अधिकारियों के प्रवेश-के लिए एक योजना शुरू की थी। इसके अंतर्गत अब तक 10 महिला लड़ाकू पायलटों को कमीशन किया गया है। यह पूछे जाने पर कि महिला लड़ाकू विमान चालकों द्वारा सीमा पार या शत्रु देशों की सीमा रेखा के आस-पास लड़ाकू विमान उड़ाते समय किस तरह की सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतने के दिशा निर्देश हैं, नाईक ने बताया, %भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को निर्धारित की गई नीति के अंतर्गत सामरिक जरूरतों और संक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त और तैनात किया जाता है, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

18 लड़ाकू विमानों से घुसपैठ के बाद बोला चीन

अमेरिका से दूर रहे ताइवान

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका-ताइवान दोस्ती से चिढ़े चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लेने की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कीथ क्रैच के दौरे से बौखलाए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि शुक्रवार को लड़ाकू विमानों का ड्रिल चेतावनी देने के लिए नहीं था, बल्कि ताइवान पर कब्जे का रिहर्सल था। चीन ने शुक्रवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवानी क्षेत्र में लड़ाकू जेट समेत 18 विमान उड़ाए। कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र में यह भी कहा गया है कि ताइवान की स्वतंत्रता खत्म होने वाली है। उसने कहा है कि वह युद्द से पीछे नहीं हटता और इसके लिए उसने भारत सीमा का भी जिक्र किया है। चीनी अखबार ने अमरिकी दौरों को लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि हर बार जब कोई अमेरिकी अधिकारी ताइवान आए तो पीएलए के लड़ाकू

विमानों को आइलैंड की ओर और आगे बढ़ना चाहिए और यदि अमेरिका के विदेश या रक्षा मंत्री ताइवान आते हैं तो इसके लड़ाकू विमान आइलैंड के ऊपर उड़ें और मिसाइलें राष्ट्रपति ऑफिस के ऊपर से। यदि ताइवान प्रशासन आक्रामकता दिखाता है तो यह सच होगा। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि इस सैन्य अभ्यास ने दो अहम सिग्नल भेजे हैं। पहला यह कि यह विरोध अमेरिका और ताइवान के बीच मिलीभगत को लेकर है। दूसरा यह कि पीएलए की प्रतिक्रिया बेहद तेज है। ताइवान और अमेरिका ने तब तक क्रैच के दौरे को गोपनीय रखा जब तक वे विमान में सवार नहीं हो गए। वह गुरुवार को ताइवान पहुंचे। पीएलए की ओर से अडवांस में सैन्य अभ्यास का ऐलान नहीं किया गया था। युद्धाभ्यास का फैसला आखिरी मिनटों में लिया गया। इससे बता दिया गया है कि चीन बड़ी कार्रवाई को बेहद कम समय में अंजाम दे सकता है। यद दिखाता है कि पीएलए के पास ताइवान के खिलाफ बेहद कम समय में एक्शन की क्षमता है। शी चिनपिंग के मुखपत्र ने कहा है कि इस और पुराने युद्धाभ्यासों से पीएलए ने ताइवान पर हमले का अनुभव हासिल कर लिया है। यह ताइवान पर कब्जे को लेकर रिहर्सल है। केवल एक राजनीतिक वजह की आवश्यकता है जिससे ये अभ्यास वास्तविक युद्ध में बदल जाएंगे। ताइवान स्ट्रेट में अशांति की सबसे बड़ी वजह अमेरिका से उसकी दोस्ती है। अमेरिका को यहां दे दूर रखने के लिए सैन्य सहित कोई भी कदम उठाया जा सकता है। चीनी सरकारी मीडिया ने कहा कि ताइवान और अमेरिका स्थिति का गलत आकलन ना करें यह ना मानें कि यह अभ्यास दिखावा है। यदि वे उकसाते रहे तो युद्ध होना तय है।

लोकसभा चुनाव की तरह बिहार विधानसभा में राजद का सफया तयः शहनवाज हुसैन

पटना, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने शनिवार को यहां दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह ही राजद का आगामी विधानसभा चुनाव में सफया हो जाएगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग बड़ी जीत साबित करेगी। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हुसैन ने 15 वषरें में बिहार के विकास का आंकड़ावार विवरण देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने नामुमकिन को मुमकिन किया है। नीतीश कुमार को देश का सबसे अनुभव वाला मुख्यमंत्री बताते हुए कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और लोकसभा चुनाव की तरह तकरीबन 100 प्रतिशत सीटें हम जीतेंगे। राजद लोकसभा में खाता भी नहीं खोल पाए, हम इस बार भी अपने विरोधियों को जीरो पर आउट करेंगे। उन्होंने कहा कि जिसे बिहार का विकास नहीं दिखता उसे जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले हुए लोकसभा चुनाव में राजद का खाता नहीं खुल पाया था और अब बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार को प्यार करने वाले प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में बिहार को कई तोहफे दिए हैं। बिहार के लोग नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे।

हुसैन ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर ही चुनाव मैदान में जाएगी और केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यो को लोगों को बताएगी। उन्होंने राजग में किसी तरह के मनमुटाव से इनकार करते हुए कहा कि राजग में दिल मिले हुए हैं, सभी सीटों पर राजग चुनाव लड़ेगी।

ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अगले हफ्ते पुणे में होगा शुरू

नयी दिल्ली, एजेंसी। ऑक्सफोर्ड की तरफ से तैयार और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए जा रहे कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अगले हफ्ते पुणे के ससून जनरल अस्पताल में शुरू होगा। राज्य सरकार की तरफ से संचालित ससून जनरल अस्पताल के डीन डॉक्टर मुरलीधर टाम्बे ने यह बात समाचार एजेंसी पीटीआई को बताई। उन्होने कहा, कोविशील्ड वैक्सीन का ससून अस्पताल में अगले हफ्ते ट्रायल शुरू हो जाएगा। यह सोमवार से शुरू हो सकता है। ट्रायल के लिए कुछ वॉलेंटियर्स पहले ही आगे आ चुके हैं। करीब 150 से 200 लोगों को इस वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। उन्होंने कहा, शनिवार से अस्पताल में ट्रायल के लिए वालेंटियर्स नामांकन शुरू हो जाएगा। जो लोग वैक्सीनेशन ट्रायल के इच्छुक हैं उन्हें अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। दूसरे चरण का ट्रायल शहर के ही भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और केईएम अस्पताल में किया गया था। ऑक्सफोर्ड की तरफ से तैयार कोविड-19 को बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ब्रिटिश-स्वीडिश कंपनी एस्ट्रेजेनिका के साथ साझेदारी है। इससे पहले, सीरम इंस्टीट्यूट ने देश में वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल रोक दिया था। वैक्सीन के चलते अप्रत्याशित बीमारी के लक्षण दिखने के बाद एस्ट्रेजेनिका ने अन्य देशों में इसका ट्रायल रोक दिया था। इसके बाद इग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 11 सितंबर को सीरम इंस्टीट्यूट ने दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को रोकने के निर्देश दिए थे।

बिजली-पानी के बिल में 50 प्रतिशत की छूट- व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत

जम्मू और कश्मीर के लिए 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान

श्रीनगर एजेंसी। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शनिवार को राज्य के लिए 1350 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। इस आर्थिक पैकेज से जम्मू और कश्मीर में व्यापार और इससे जुड़े क्षेत्रों को गति दी जाएगी, जिससे वह कोरोना के कारण हुए भारी नुकसान से उबर सके। सिन्हा के इस ऐलान के बाद से केंद्र शासित प्रदेश के कारोबारी उत्साहित है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर किया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है इसके साथ कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने लिए हैं जिससे आवाम को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है। उन्होंने दावा किया की राज्य के लिए यह एक बड़ी राहत साबित होगी और इसकी मदद से यहां नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे।

उन्होंने आगे बताया की सरकार ने तय किया है कि जम्मू-कश्मीर में 5 फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे-बड़े उधार लेने वाले व्यापारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा हैं। यह सुविधा चालू वित्त वर्ष में छह महीने के लिए होगी। इसमें 950 करोड़ रुपये का जम्मू-कश्मीर प्रशासन सीधे तौर पर मदद कर रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस पैकेज के तहत सरकार ने एक साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50 फीसदी की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए खर्च होगा। जबकि किसान, आम परिवार, व्यापारी सबके लिए यह फैसला किया गया है। जबकि सभी उधारकर्ताओं के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई। वहीं, अच्छे मूल्य निर्धारण और पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जे-के बैंक द्वारा अनुकूलित स्वास्थ्य-पर्यटन योजना तैयार की गई है। 1 अक्टूबर से जे-के बैंक युवाओं और महिला उद्यमों के लिए एक विशेष डेस्क शुरू करेगा।

योगी ने कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं उपचार की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के दिए निर्देश

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं उपचार की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मृत्यु की दर कम और रिकवरी दर अच्छी है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के साथ-साथ बैकअप की व्यवस्था भी रहनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑक्सीजन निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, झांसी, अयोध्या, मेरठ तथा गोरखपुर की विशेष मॉनिटरिंग करते हुए इन जिलों में उपचार व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। उन्होंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से जनपद कानपुर नगर की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि अब कानपुर नगर में शत-प्रतिशत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-संजीवनी एप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही ओ0पी0डी0 सुविधा काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेवा से लाभान्वित हो सके, इसके दृष्टिगत ई-संजीवनी एप का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान जारी रखा जाए। इसके लिए प्रचार के विभिन्न साधनों के साथ-साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने मेडिकल टेस्टिंग, डोर-टू-डोर सर्वे तथा कॉन्टैक्ट टेऊसिंग के कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाया रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफनियमित राउण्ड लें। पैरामेडिक्स द्वारा मरीजों की गहन मॉनिटरिंग की जाए। एम्बुलेंस सेवाओं को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश सी0 अवस्थी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

वर्षा का जल संचय कर खारे पानी की समस्या को समाप्त किया जा सकता किया जा सकता है

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष आज यहां उनके सरकारी आवास पर 'जल जीवन मिशन हर घर जल' व 'अटल भूजल योजना' के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी योजनाएं समय से और मानक के अनुसार पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि जो पेयजल योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उनमें त्वरित गति से कनेक्शन देने की कार्यवाही भी की जाए, जिससे लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत बुन्देलखण्ड की सम्पूर्ण आबादी, विन्ध्य क्षेत्र की सम्पूर्ण आबादी, आर्सेनिक,फ्लोराइड तथा जे0ई0,ए0ई0एस0 से प्रभावित आबादी, 08 आकांक्षात्मक जनपदों तथा शेष प्रदेश में वर्ष 2022 तक हर हाल में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने लक्षित क्षेत्रों में तेजी से कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक 15 दिन पर कार्य की प्रगति की अद्यतन स्थिति से उन्हें अवगत कराया जाए।

ट्रान्सफर पोस्टिंग में पूर्व डीजीपी ओपी सिंह की भूमिका की जाँच की मांग

लखनऊ, संवाददाता। एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने पैसे पर आईपीएस तथा अन्य पुलिस अफसरों के ट्रान्सफर पोस्टिंग की शिकायतों में पूर्व डीजीपी ओ पी सिंह की भूमिका की जाँच की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे अपने पत्र में नूतन ने कहा कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में आईपीएस अफसर अजयपाल शर्मा तथा हिमांशु कुमार द्वारा मेरठ तथा आगरा जैसे जिलों की पोस्टिंग के लिए दलालों को 60-80 लाख रुपये देने तथा अन्य जिलों के पोस्टिंग के रेट की बात कही है। उन्होंने कि इन बातों से स्पष्ट है कि उस समय विभिन्न पोस्टिंग के लिए तय रेट थे, जो सबों को ज्ञात थे. यह भी सर्वविदित है कि डीजीपी के रूप में अपनी तैनाती के समय ओ पी सिंह बहुत ताकतवर थे. उस समय यह चर्चा बहुत जोरों से उठी थी कि तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार उनके ट्रान्सफर पोस्टिंग की संस्तुतियों में बाधा बन रहे थे, जिसके कारण दोनों अफसरों में भारी मतभेद व विवाद हुआ था. इसमें भी ओ पी सिंह भारी पड़े थे तथा अरविन्द कुमार को गृह विभाग से हटना पड़ा था। नूतन ने कहा कि इन सभी तथ्यों से पुलिस अफसरों के इस प्रकार के ट्रान्सफर-पोस्टिंग में ओ पी सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. अतः उन्होंने ओ पी सिंह के डीजीपी रहते पुलिस अफसरों के भारी संख्या में किये गए ट्रान्सफर एवं पोस्टिंग की जाँच इस संबंध में बनाये गए नियमों के आलोक तथा गलत ढंग से हुए ट्रान्सफर के आरोपों के सन्दर्भ में किये जाने की मांग की है।

चीन निर्मित सामग्री बहिष्कार दिवस पर सेनानी कोरोना को लेकर सरकार की गाइड लाइन का पालन करें: यशवन्त सिंह

लखनऊ, संवाददाता। लोकतन्त्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक विधानपरिषद सदस्य यशवन्त सिंह ने कहा है कि 21 सितम्बर को चीन निर्मित सामग्री बहिष्कार दिवस के अवसर लोकतन्त्र सेनानी कोरोना को लेकर जारी उत्तर प्रदेश सरकार की गाइड लाइन का पालन अवश्य करें। इसे लेकर किसी तरह की लापरवाही लोकतन्त्र सेनानियों की मर्यादा के विपरीत है। धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, लोकतन्त्र सेनानी कल्याण समिति के अध्यक्ष रामसेवक यादव, श्री चन्द्रशेखर ट्रस्ट के प्रबंधक बृजेश कान्दू, कोषाध्यक्ष लालबहादुर सिंह से बातचीत में सेनानी समिति के संरक्षक यशवन्त सिंह ने कहा कि शालीनता, संकल्प, साहस और स्वअनुशासित आचरण ही हम लोकतन्त्र सेनानियों की पहचान है। चीन को लेकर व्याप्त क्रोध के बीच भी बहिष्कार दिवस के कार्यक्रमों में हमारी यह पहचान झलकनी चाहिए कि हम लोकतन्त्र सेनानी हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम कोरोना को लेकर जारी सरकार की गाइड लाइन का पालन अवश्य करें। उन्होंने कहा कि हम पिछले पांच साल से चीन निर्मित सामग्री बहिष्कार के लिए कदम से कदम मिलाकर जुलूस निकालते हैं, सभा करते हैं और संकल्प लेते हैं लेकिन इस वर्ष यह करना जोश में होश खोने जैसा होगा। ऐसा न हो, इसे लेकर संगठन के पदाधिकारियों को विशेष ध्यान देना होगा।विधानपरिषद सदस्य यशवन्त सिंह ने कहा कि यूपी देश का पहला राज्य है जहाँ चीन की कम्पनियाँ किसी निविदा में भाग नहीं के सकती हैं, जहाँ वन डिस्टिक-वन प्रोडक्ट योजना के तहत देशी उत्पादों को सरकार की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है। लोकतन्त्र सेनानी कल्याण समिति और श्री चन्द्रशेखर ट्रस्ट को इसके लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए।

इंदिरा नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, ऑन लाइन होती थी बुकिंग

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए युवक और युवतियों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, लग्जरी कार, मोटरसाइकिल, 13 मोबाइल फोन, 6820 रुपये, तीन लेडीज पर्स, तीन पुरुषों के पर्स, 3 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से 7 युवतियों और पांच युवकों को हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया। एडीसीपी उत्तरी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि सेक्स रैकेट चलने की शिकायत पर डीसीपी उत्तरी शालिनी सिंह ने एसीपी अलीगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था। टीम ने रात में छापेमारी करके इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी पुरम स्थित शिवानी विहार में एक मकान पर छापेमारी कर 7 युवतियों और मकान मालिक सहित पांच पुरुषों को मौके से गिरफ्तार किया।

चिनहट में भीषण सड़क हादसा बाइक डिवाइडर से टकराने से युवक की हालत गंभीर

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। यूपी के चिनहट से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। शनिवार की सुबह लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र के दुधरा गांव के पास किसान पथ हाइवे पर एक बाइक डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतना भीषण था, कि युवक हवा में उछलकर दूर डिवाइडर पर जा गिरा। उसका सिर डिवाइडर से टकराया और दो टुकड़े हो गए। पीछे से जब घायल युवक का जानकार मौके पर पहुंचा तो उसने अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसकी इलाज चल रही है। कोतवाली पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घायल युवक रमाकांत गांव गंगागंज गांव का रहने वाला हैं। वह बाइक से अपने साथी के साथ किसान पथ हाईवे से अपने घर जा रहा था। अचानक बाइक से डिवाइडर जा टकराई। जिससे पीछे बैठे साथी को गंभीर चोटें आई है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक की तहरीर पर डिवाइडर चालक के खिलाफमुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है।

संजय सिंह आज हजरतगंज थाने में होंगे पेश,राजद्रोह का मामला किया गया था दर्ज

लखनऊ, संवाददाता। आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्य सभा सांसद संजय सिंह अपने खिलाफ दर्ज मामले में रविवार को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में पेश होंगे। पार्टी के प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ''संजय सिंह अपने खिलाफ दर्ज मामलों में रविवार को हजरतगंज पुलिस थाने में पेश होंगे और गिरफ्तारी देंगे।'' एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हजरतगंज पुलिस थाने में आप नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दो सितंबर को मामला दर्ज किया गया था। सिंह के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज मामले में राजद्रोह की धारा जोड़ी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिंह के खिलाफ दो सितंबर को एक सर्वेक्षण कराये जाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 501 ए तथा 120 बी के अलावा आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था। अधिकारी ने बताया कि सिंह को लखनऊ पुलिस ने बृहस्पतिवार को एक नोटिस भेजा जिसमें अन्य धाराओं के अलावा राजद्रोह की धारा 124 ए को भी शामिल किया गया है। यह नोटिस संजय सिंह के दिल्ली वाले आवास के नार्थ एवेन्यू के पते पर भेजा गया है। हजरतगंज पुलिस थाने के जांच अधिकारी ए के सिंह की ओर से संजय सिंह को भेजे गए नोटिस में कहा गया है, आपके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 242ध्2020 भारतीय दंड संहिता की धारा 153 एध्153 बीध्,505 (1) (बी)ध्505(2)ध्468ध्469ध्124 एध्120 बी व 66 सीध्66 डी आईटी अधिनियम के तहत पुलिस थाना हजरतगंज लखनऊ के संबंध में जांच विवेचना की जा रही है, जो संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है, जिसके संबंध में अपने पक्ष में तथ्योंध्अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मेरे समक्ष बीस सितंबर को सुबह 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। नोटिस में कहा गया है, ''यदि आप नियत तिथिध्समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही की जायेगी। जांच अधिकारी ने बताया कि संजय सिंह के अलावा सर्वेक्षण करने वाली निजी कंपनी केखिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सिंह द्वारा जारी किये गये इस सर्वेक्षण में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ सरकार एक विशेष जाति के लिये कार्य कर रही है। इस सर्वेक्षण के बाद संजय सिंह के खिलाफप्रदेश के विभिन्न जिलों में कम से कम 13 मामले दर्ज कराये गये थे।

स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छ स्टेशन दिवस का आयोजन

लखनऊ, संवाददाता। भारतीय रेल पर आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने इस पखवाड़े के चतुर्थ दिवस पर स्वच्छता एवं साफसफाई संबंधी कार्यकलापों तथा गतिविधियों को साकार स्वरुप प्रदान करते हुए शनिवार को स्वच्छ स्टेशन दिवस के रूप में मनाया गया, इस दिवस विशेष पर मंडल के ए-1 एवं ए श्रेणी के स्टेशनों की स्वच्छता एवं साफ सफाई के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यकलापों को अत्यंत क्रमबद्ध एवं सुनियोजित प्रारूप में कार्यान्वित किया गया, जिसके अंतर्गत इन स्टेशनों पर स्वच्छता से सम्बंधित उपकरणों एवं संयंत्रों की उपलब्धता एवं उनकी क्रियाशीलता, स्वच्छता संयंत्रों एवं औजारों के उचित रखरखाव तथा सुरक्षासंबंधी व्यवस्था, कूड़े एवं कचरे का वर्गीकरण के आधार पर संग्रह एवं निस्तारण हेतु डस्टबिनों की उपलब्धता, शौचालयों की साफसफाई एवं पानी के निकास संबंधी व्यवस्था जैसे विशेष बिन्दुओं सहित सम्पूर्ण स्टेशन एवं परिसर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता का अभियान संचालित किया गया, निरंतर संचालित होने वाले इस पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न तिथियों में क्रमबद्ध रूप से सम्पूर्ण मंडल पर इस अभियान को अत्यंत सुनियोजित एवं योजनाबद्ध प्रारूप के आधार पर संचालित करने का प्रावधान किया गया है।

सपा ने बूथ स्तर पर पदाधिकारियों की बैठक करने के दिए निर्देश

लखनऊ, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आज उन्नाव और देवरिया जिले के जिलाध्यक्षों, विधानसभा अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों से वर्चुवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश कार्यालय प्रभारी श्री अरविन्द कुमार सिंह मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा और देवरिया जिले की देवरिया सदर विधान सभा क्षेत्र के सम्भावित उपचुनाव को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ इस विधानसभा क्षेत्रों के सेक्टर प्रभारियों से बात कर बूथों की जानकारी ली। बूथ स्तर पर पदाधिकारियों की बैठक करने के निर्देश दिए। दोनों जिलों में संगठन को मजबूत करने का निर्देश देते हुए समस्याओं की जानकारी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने नेताओं से कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए तकनीक की मदद से आम कार्यकर्ता से संवाद बनाते हुए उन्हें सक्रिय रखा जाए। कार्यकर्ता सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करते हुए जनता के सुख-दुःख में साथ देने का काम करें। जनता भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली से निराश हो चुकी है। लोग परेशान है। संकट में है। जनता को समाजवादियों से ही उम्मीद है। लोगों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पर भरोसा है। नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार के किसान नौजवान विरोधी कार्यों को उजागर करें। लोगों को समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव द्वारा सरकार के समय किए गए कार्यों को बताएं। सभी नेता कार्यकर्ता प्रदेश में रिक्त विधानसभा सीटों पर सम्भावित उपचुनाव और 2022 के आम विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करते हुए लोगों को भाजपा की झूठ और धोखे की राजनीति की सच्चाई बताएं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश कार्यालय प्रभारी अरविन्द कुमार सिंह मौजूद रहे।

बुर्ज खलीफा में जमीन दिलाने का झांसा देने वाला गिरफ्तार

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी की गोसाईगंज पुलिस ने दुबई के बुर्ज खलीफा में जमीन दिलाने का झांसा देने वाले अलास्का कम्पनी के सरगना हरिओम यादव को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। हरिओम के गिरोह ने सैकड़ों लोगों से जमीन दिलाने के नाम पर 59 करोड रुपये की धोखाधड़ी की थी। इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि हरिओम को चांद सराय के पास से पकड़ा गया है। आरोपी 10 जून को परिवार संग शहर छोड़ कर फरार हुआ था। जिसकी तलाश में कई टीमें लगी थीं। इण्टर पास हरिओम कुछ साल पहले तक चाय का होटल चलाता था। इंस्पेक्टर के अनुसार गिरोह में शामिल छह लोगों फरार हैं। जिन्हें पुलिस तलाश रही है। वहीं, अलास्का कम्पनी के सात बैंक खाते भी सीज कराये गये हैं।

यूपी एसटीएफके हत्थे चढ़ा पशुपालन विभाग में 10 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का एक सदस्य

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पशुपालन विभाग में फर्जी टेण्डर के माध्यम से धोखाधड़ी कर नौ करोड़ 72 लाख रूपये की ठगी करने वाले गैंग के एक सदस्य आरोपी संतोष मिश्र को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी कर नौ करोड़ 72 लाख रूपये की ठगी करने वाले गैंग के सदस्यों के खिलाफपुलिस ने मामला दर्ज किया था। एसटीएफने इस मामले के एक आरोपी संतोष को शुक्रवार रात राजधानी स्थित इन्दिरा नहर के पास चिनहट क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी संतोष पुत्र स्वर्गीय सत्यनारायण मिश्र, गोंडा के धानेपुर क्षेत्र में मिश्रनपुरवा गांव का निवासी है। वह वर्तमान में लखनऊ के गोमतीनगर में रह रहा है।

हिंदी पखवाड़े में निराला को स्मरण करते परिचर्चा का आयोजन

लखनऊ, संवाददाता। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ मंडल पर चल रहे राजभाषा पखवाड़े के अंतर्गत प्रत्येक दिवस पर मंडल के अनेक स्थानों पर राजभाषा संबंधी विभिन्न कार्यकलापों को कार्यान्वित करने का प्रावधान किया गया है एवम् इसी के अनुक्रम में शनिवार को मंडल के जौनपुर जंक्शन पर हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रख्यात एवम् हिंदी साहित्य के देदीप्यमान पुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी की रचनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनकी अनेक कविताओं का सस्वर पाठ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित रेल कर्मियों ने भी कविताएं, छंद व दोहे आदि सुनाकर अपनी साहित्य प्रतिभा एवम् रुचि का दर्शन कराया। इस कार्यक्रम को जौनपुर जंक्शन पर स्थित निराला हिंदी पुस्तकालय में आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त इस सभा में राजभाषा के प्रचार प्रसार पर चर्चा करते हुए आपसी विचार विनिमय द्वारा राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास एवम् महत्ता पर वार्तालाप करते हुए उपस्थित रेलकर्मियों से अपने दैनिक जीवन एवम् रेलसेवा में अधिकाधिक हिंदी के प्रयोग की अपेक्षा की गई। कोविड 19 के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए इस आयोजन में अनेक सदस्यों ने ऑन लाइन माध्यम से भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करी।

भाजपा सरकार की नीतियां किसान और नौजवान विरोधी: अखिलेश यादव

लखनऊ, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियां किसान और नौजवान विरोधी है। भाजपा सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। यह सरकार खेती को अमीरों के हाथों गिरवी करने के लिए शोषणकारी विधेयक लायी है। ये खेतों से किसानों का मालिकाना हक छीनने का षडयंत्र है। इससे एमएसपी सुनिश्चित करने वाली मंडियां धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। भविष्य में किसानों की उपज का उचित दाम भी छिन जाएगा और वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन कर रह जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया बिल किसान विरोधी है, यह किसानों के साथ बड़ी साजिश है। कृषि और किसान ही होता है जो कठिन समय में देश की अर्थव्यवस्था सम्हालता था। लेकिन अब खेती पर बड़े उद्योगपतियों की नजर है। जिससे किसान मजदूर बन कर रह जाएगा। किसानों की खेती बर्बाद हो जाएगी। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आयी है, उसने अपनी नीतियों और कार्यों से किसान को त्रस्त कर रखा है। अभी धान की फसल में यूरिया और अन्य उर्वरक डालने के लिए किसान मारा-मारा फिर रहा था। यूरिया खाद की जमकर कालाबाजारी हुई। किसान को मंहगे दामों पर यूरिया खरीदनी पड़ी। गन्ना किसानों की परेशानी जस की तस है। नया पेराई सत्र आने वाला है, लेकिन पिछले सत्र का 15 हजार करोड़ रूपया बकाया है। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर सरकार चुप्पी साध लेती है। सरकार और मिल मालिकों की सांठ-गांठ से गन्ना किसान संकट में है। इसी तरह से भाजपा नौजवानों को लगातार धोखा दे रही है। भाजपा ने चुनाव के समय नौकरियों के नाम पर युवाओं से कितना झूठ बोला यह अब पता चल रहा है। नौजवान, किसान तथा आम आदमी भाजपा की धोखे की राजनीति को समझ रहा है। भाजपा सरकार में प्रदेश और देश में मंहगाई आसमान छू रही है। कोरोना काल में जबकि हर व्यक्ति आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लोगों की जेब खाली है। ऐसे में खाने-पीने की चीजों व सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि ने जनता के सामने नया संकट पैदा कर दिया है। भाजपा की नीतियां लोककल्याणकारी नहीं है।

मेधावी छात्र के इलाज के लिये योगी ने दी 10 लाख की मदद

लखनऊ, संवाददाता। ब्लड कैंसर की बीमारी से जूझ रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के शोध छात्र के इलाज के लिये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियम शिथिल कर दस लाख रूपये की मदद दी है और चिकित्सकों से छात्र के बेहतर इलाज की अपील की है। दरअसल, आईआईटी रूड़की में मशीन लर्निंग एंड आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस विषय पर शोध कर रहे 27 साल के आशीष दीक्षित ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं जिनका इलाज लखनऊ पीजीआई में चल रहा है। पिता अशोक दीक्षित ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगायी थी कि इकलौते पुत्र के इलाज में दस लाख रूपये खर्च हो चुके हैं लेकिन दिमाग में रक्त के थक्के जमा होने और संक्रमण के कारण इलाज अभी और लंबा चलेगा। चिकित्सकों ने 12 लाख रूपये का इंतजाम करने को कहा है। वनकर्मी अशोक दीक्षित का पत्र मिलते ही श्री योगी ने मेधावी के इलाज के दस लाख रूपये की मदद की और परिवार से खुद संपर्क कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

कुर्सी रोड स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस सप्ताह पर पौधारोपण करते मंत्री उपेंद्र तिवारी

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेल्फरेगुलेशन का वायरस

गेरहार्ड श्रोएडर 2002 में जर्मनी के चांसलर थे। उनके बालों के बारे में जर्मनी की एक समाचार एजेंसी ने खबर चला दी कि वे उसे रंगते हैं। डीडीपी न्यूज एजेंसी ने यह ख़बर एक जर्मन महिला के बयान के हवाले से दी थी, जिसमें उसने कहा था कि चांसलर श्रोएडर अपने बाल काले रंग से डाई इसलिए करते हैं, ताकि वो थोड़ा डार्क से दिखें। समाचार एजेंसी ने बिना चांसलर कार्यालय से स्पष्टीकरण लिये, यह ख़बर चला दी थी। 58 वर्षीय चांसलर श्रोएडर के बाल जर्मन राजनीति में जरे बहस था, क्योंकि इस खबर से नाराज चांसलर ने हेमबर्ग की अदालत में केस कर दिया था। अदालत की पाबंदियों के बावजूद न्यूज एजेंसी की यह खबर कई अखबारों में छप चुकी थी। रेडियो और टीवी वाले भी किसी न किसी बहाने उसकी चर्चा कर चुके थे। अदालत में चांसलर श्रोएडर के हेयर ड्रेसर उडो वाल्ज को भी हाजिर किया गया। जिसने बयान दिया कि वो बिल्कुल बाल नहीं रंगते। ऐसा होता तो सबसे पहले मेरी जानकारी में आता। कोई पांच महीने तक बाल पर बवाल होता रहा। चांसलर श्रोएडर मई 2002 में यह केस जीत गये। मगर, उसी समय स्टर्न मैगजीन ने अपने कवर पर चांसलर श्रोएडर की नंगी तस्वीर छाप दी, जिसमें बड़ के पत्ते से केवल उनके प्राइवेट पार्ट को ढंका दिखाया गया था। उस पत्ते के आधे हिस्से पर लाल कपड़े का एक टुकड़ा दिखाया गया, जो गठबंधन सरकार समर्थक एसपीडी और ग्रीन पार्टियों को प्रतिबिंबित कर रही थी। मैगजीन का शीर्षक था- श्नंगा सचश् (दी नाक्टे वाहरहाइट)! उसके नीचे उप शीर्षक था, क्या श्रोएडर फिर भी जीत जाएंगे? चांसलर श्रोएडर स्टर्न मैगजीन के विरूद्ध अदालत नहीं गये, क्योंकि वह तस्वीर असली थी। मगर, श्रोएडर की पार्टी के लोग और उनके शैदाइयों ने इतना जरूर कहा कि यह तस्वीर बैड टेस्ट वाली है। इस घटना के 18 साल के भीतर जर्मन मीडिया बदला है। उसकी जिम्मेदारियां, और दुश्वारियां भी बदली हैं। 1 मार्च 2007 को जर्मनी में टेलीमीडिया एक्ट (टीएमजी) लागू हुआ। उससे पहले टेलीसर्विस एक्ट, टेलीसर्विस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इंटरस्टेट ट्रिटी ऑन मीडिया सर्विस, इंटरस्टेट ट्रिटी ऑन ब्रॉडकॉस्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंसन एक्ट (टीकेजी) मीडिया को अपने तरीके से निर्देश देने का काम कर रहे थे। कई भाषाओं में प्रसारण करने वाले डायचेवेले रेडियो-टीवी और डॉयचलांड रेडियो ये दो ऐसी संस्थाएं सरकार द्वारा संचालित हैं, जिनके लिए नियम कायदे वहां संबंधित मंत्रालय ने ही तय कर रखा है। बाकी 200 से अधिक प्राइवेट रेडियो स्टेशन, केबल, सेटेलाइट टेलीविजन, प्रिंट मीडिया राज्यों में स्थापित नियम-कायदे की परिधि में आते रहे हैं, जिन्हें एक देश-एक क़ानून के तहत लाने के प्रयास पिछले डेढ़ दशक से चल रहे थे। इस बीच डिजीटल प्लेटफार्म, सोशल मीडिया की तेजी ने समूचे यूरोप में फेक न्यूज को रोकने की चुनौती खड़ी कर दी। जर्मनी में 10 फीसद वैसे अखबार-मैगजीन किसी न किसी राजनीतिक दल को समर्थन करते दिखते हैं। बाकी मीडिया वैचारिक रूप से स्वतंत्र ही रहा है। जर्मन सरकार का एक इदारा है, बुंडेसकार्टेल आम्ट (संघीय कार्टेल कार्यालय) यह ऑफिस मीडिया संबंधी शिकायतों की भी सुनवाई करता है। इससे अलग 1956 में स्थापित जर्मन प्रेस कौंसिल ने कुछ गाइडलाइन तय कर रखी है। शिकायतें भी सुनती है जर्मन प्रेस कौंसिल। मगर, इन दोनों महकमों और 1 मार्च 2007 से लागू श्टेलीमीडिया एक्टश् (टीएमजी) से जर्मन मीडिया नियंत्रित हो रहा था क्या? जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, उसका उत्तर ना में ही देते हैं। अब हुआ यह कि 9 दिसंबर 2019 को जर्मन राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों ने यूरोपीय संघ द्वारा आहूत श्ऑडियो विजुअल मीडिया डायरेक्टिवश् को लागू करने पर अपनी सहमति दे दी। इस नये क़ानून को अंतरराज्यीय मीडिया संधि (मीडियनस्टाड्स-फ रट्राग) बोलते हैं। संक्षेप में इसका नाम है, श्एमएसटीवीश! सितंबर 2020 तक जर्मनी के सभी राज्य श्एमएसटीवीश् को लागू कर देंगे। इसके तहत ब्रॉडकास्ट मीडिया, ऑन लाइन सेवाएं जिसमें संपादन से लेकर खबरें परोसने तक की जो जिम्मेदारी यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग ने तय कर दी है, उसे जर्मनी के सभी राज्यों में भी लागू कर दिया जाएगा।

इसमें ऐसा नहीं कि जो लोग ग्राफिक्स बनाते हैं, या जिनके वायस ओवर व कार्टून जा रहे हैं, ऐसे सेवा प्रदाता इस जिम्मेदारी से बाहर हैं। वीडियो शेयरिंग प्लेटफार्म तथा ग्राफिक्स इंटरफेस वाले भी इसमें शामिल किये गये हैं। यूरोपीय संघ ने पूरी समग्रता में मीडिया जिम्मेदारी का यह खाका तैयार किया है। इस कवायद में पूरे पांच साल लगे हैं। 2015 से ही यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों में मीडिया रेगुलेशन के वास्ते सर्वे व विमर्श का सिलसिला जारी था। इसमें सबसे बड़ी चुनौती यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों में लागू करवाने की रहेगी। आपने मीडिया के लिए विनियमन तय कर दिया, और मुक्त हो गये? ऐसा भी नहीं है। यूरोपीय संघ लोगों को चेतनशील करने की मुहिम में भी लगा हुआ है,ताकि लोग इस बात से जागरूक हों कि जो सामग्री वो देख पढ़ रहे हैं, उससें कोई झोल-झाल तो नहीं है। 2018 में यूरोबैरोमीटर सर्वे-6 के जरिये सभी सदस्य देशों ने जानकारी दी थी कि 83 फीसद फर्जी खबरें उन्हें परोसी गई थीं। यूरोपीय संघ ने इसे लोकतंत्र के वास्ते एक बड़ा खतरा माना था। इस सड़ांध और सूचना विकार को कैसे फिल्टर करें, इसे समझने के वास्ते 2017 में कौंसिल ऑफयूरोप ने सात सदस्यीय हाई लेबल एक्सपर्ट ग्रुप (एचएलईजी) का गठन किया था, जिसमें अकादमिक, न्यूज मीडिया, सोशल नेटवर्किंग वाले, सिविल सोसाइटी के लोग, और पत्रकारों को शामिल किया गया था। एचएलईजी ने मार्च 2018 में एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी, जिसने एक उपाय यह भी सुझाया था कि मीडिया अज्ञानता, श्डिसइंफर्मेशनश् को दूर करना आवश्यक है। लोग जब चेतनशील होंगे, तो ब्राडकास्टिंग में होने वाली बेईमानी को भी पकड़ पायेंगे। उस श्यूरोबैरोमीटर सर्वे-6श् में मैसेडोनिया के एक छोटे से कस्बे वेलेसवायरस को बतौर उदाहरण पेश किया गया, जहां 140 ट्रंप समर्थक न्यूज वेबसाइट खोले गये थे। सोचिये, अमेरिका से लगभग सवा नौ हजार किलोमीटर दूर मैसेडोनिया के एक छोटे से कस्बे का यूएस चुनाव से क्या लेना-देना? कुछ तो खेल होने वाला है, तभी एक अनजान से कष्स्बे में ट्रंप समर्थक 140 वेबसाइट खोले गये। अब भारत में यह पता लगाने का विषय है कि ट्रंप समर्थक कितने हजार वेबसाइट खोले गये? यहां तो खुला खेल फर्रूखाबादी चल रहा है।

न्यूयार्क स्थित डिजीटल मीडिया पर काम करने वाली संस्था है, श्बजफीड-श्रीश। उसकी एक रिपोर्ट चौंकाने वाली रही है कि जर्मन चांसलर आंगेला मैर्केल से संबंधित जो विश्लेषण पिछले पांच वर्षों में ग्लोबल स्तर पर जारी हुए, उनमें दस में से केवल एक विश्वसनीय था, सात न्यूज एनालिसिस फर्जी होते थे, दो पर्सनल ओपिनियन होते थे। फेक न्यूज के इस खेल को पूरी दुनिया के स्तर पर देखेंगे, तो नाले की दुर्गंध और उसका बजबजाना भी उसके आगे फीका लगेगा। एक बात तो मानकर चलिये कि अमेरिकी चुनाव में यह और घिना जाएगा। नार्डिक देश फेक न्यूज को फिल्टर करने में जी-जान से लगे हैं। वहां स्कूली बच्चों का यूनिसेफ की मदद से बताया जा रहा है कि वे सही और गलत खबरों को पहचाने। मीडिया के प्रति लोगों को कैसे चेतनशील बनाया जाए, इस मुहिम में ब्रिटिश संस्था आफकॉम ने मिडिया लिटरेसी कार्यक्रम 2003 से चला रखा है।

मगर, क्या हम भारत को श्मीडिया लिटरेटश् देश मानें? यूरोपीय संघ और नार्डिक देशों जैसा कोई समग्र सर्वे नहीं दिखता कि 46 करोड़ इंटरनेट यूजर्स,62 करोड़ 70 लाख टीवी व्यूवरशिप वाले इस देश में मीडिया गतिविधियों की समझ कितने प्रतिशत लोगों को है? कितने लोगों को इसका शउर है कि बीच बहस में न्यूज चौनल का एंकर किसके इशारे पर प्रतिद्वंद्वी गेस्ट की आवाज को म्यूट कर देता है। क्यों सत्तापक्ष के प्रवक्ता, और विश्लेषक शो के दौरान बाकी गेस्ट से अधिक समय पाते हैं, और उसके प्रतिद्वंद्वी चंद सेकेंडों में निपटा दिये जाते हैं? बात इस कपट व बेईमानी तक होती, तो भी लोग बर्दाश्त कर ही रहे थे। मगर, टेलीविजन उन्माद व नफरत फैलाने का माध्यम बन जाये, यह सुप्रीम कोर्ट तक चिंता का विषय बन गया है। यह कुछ अजीब नहीं लगता कि इस देश में सर्वोच्च अदालत को पूछना पड़ रहा है कि विजुअल मीडिया के लिए कोई मानक या गाइडलाइंस है या नहीं? संभवतरू ऐसा पहली बार हुआ कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जोसेफ व इंदू मल्होत्रा की पीठ को टीवी चौनलों की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणी करनी पड़ी,श्यह फ्री स्पीच का मुद्दा नहीं है। इस बहाने आप सिविल सेवा में मुसलमानों की घुसपैठ जैसा नफरत फैलाने वाला कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं? यों, विजुअल मीडिया कई वर्षों से बताता रहा है कि हमने अपने मानक बना रखे हैं। सेल्फ रेगुलेशन का यह वायरस विजुअल मीडिया के साथ ही आया है।

सम्पादकीय

जितनी हालत बिगड़ेगी, ट्रम्प को ही मिलेगा फायदा

इस वर्ष के प्रारम्भ में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से अमेरिका में नस्लीय समानता को लेकर विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों का सिलसिला चल पड़ा था, जिसके केन्द्र में पुलिस सुधार था। ब्लैक लाईव्स मैटर आंदोलन के कारण हुई हलचलों व तब्दीलियों को 1960 के नागरिक अधिकार युग के बाद नस्लीय न्याय की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम समझा जाता है। इसके बावजूद तीन महीने बाद 23 अगस्त को केनोशा, विस्कोन्सिन में जेकब ब्लैक पर हुई गोलीबारी से लगता है कि बहुत कुछ नहीं बदला है। ज्यादातर अन्य चर्चित हुए पुलिस अत्याचारों के विपरीत ब्लैक इस शूटआऊट में बाल-बाल बच गये। उन पर हुई शूटिंग के वीडियो से ज्ञात होता है कि पुलिस द्वारा सीमा से अधिक शक्ति का प्रयोग किये जाने का इससे बड़ा सबूत उपलब्ध नहीं हो सकता। वीडियो की शुरुआत ब्लैक के अपनी कार की ओर बढ़ने से होती है, जिनके पीछे दो पुलिस वाले आ रहे हैं जिनकी बंदूकें निकली हुई हैं। उसके बाद ब्लैक अपनी कार में बैठने के लिये आगे बढ़ते हैं तभी एक अधिकारी उन्हें पकड़ लेता है और उनके शरीर पर फायर करने लगता है। उनकी स्थिति गंभीर हो जाती हैय आखिरकार नजदीक से उन पर सात बार गोलियां चली हुई होती हैं। इस शूटिंग के परिणामस्वरूप अमेरिकी संस्कृति के सभी आयामों से दरारें पैदा होने लगीं। उस पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) ने न सिर्फ खेल आयोजन को टाल दिया बल्कि पूरा टूर्नामेंट ही रद्द करने का तक विचार किया जिसकी अनुगूंज अभी तक सुनाई दे रही है। केनोशा कस्बा रातों-रात प्रदर्शन स्थल में तब्दील हो गया जहां पर गोलीबारी हुई थी। ज्यादातर प्रदर्शनकारी तो शांत थे लेकिन अनेक दंगे भी हो गये। एक पूरी कार डीलरशिप सहित अनेक इमारतों को जलाकर खाक में मिला दिया गया। इस क्षेत्र में व्याप्त असंतोष ने हथियारबंद नागरिकों का भी ध्यान आकृष्ट किया जिन्होंने श्व्यवस्था बहालश् करने की कोशिश की। विडंबना तो यह है कि ये सिविलियन यह भूल गये कि सड़कों पर प्रदर्शनकारियों से भिड़ना श्व्यवस्थाश् बनाये रखने का सबसे खराब तरीका हो सकता है- आखिरकार एक-दूसरे से भिड़ते दो समूह शायद ही व्यवस्था बहाल कर सकते हैं, विशेषकर जब एक गुट जबर्दस्त तरीके से हथियारों से लैस हो। इन हथियारबंद नागरिकों में से एक 17 वर्षीय कायल रिटेनहाऊस असंतोष को दबाने में मदद करने के लिये पड़ोसी राज्य इलिनॉयस से हमला करने वाली भरी हुई राईफल लेकर आया था। इसका परिणाम यह हुआ कि यह हाईस्कूल का छात्र हिंसक स्थिति को सम्हाल नहीं पाया और इसके पहले कि गिरफ्तार कर उस पर हत्या का मुकदमा चले, वह दो लोगों को मार चुका था और कई को घायल भी। रिटेनहाऊस के काम के प्रतिसाद में ध्रुवीकरण हुआ। कुछ परम्परागत लोगों ने यह दावा करते हुए उसकी तारीफ की कि वह दंगों से शहर को बचाने के लिये जो कुछ भी आवश्यक था, वह करना चाहता था। हालांकि उसके काम की व्यापक आलोचना भी हुई- आखिरकार उसने कई लोगों की हत्या की थी। अधिकतर लोगों के अनुसार रिटेनहाऊस ने कई लोगों को मारा था और उसने तब व्यवस्था बनाने के लिये कुछ भी नहीं किया। उसके द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाये जाने से लोगों के घबराहट में इधर-उधर भागने से अफरा-तफरी मच गई। रिटेनहाऊस की करतूत को वैसे ही लिया गया जैसे कि कोई सामान्य ट्रम्प समर्थक लेता है- प्रदर्शन एवं उनके कारण संपत्तियों को हुआ नुकसान देश के सामने अब प्रमुख मुद्दा है, बजाय वे मुद्दे जिन्हें लेकर प्रदर्शनकारी लड़ रहे हैं। यह एक दिलचस्प तरीका है जो सतह पर काफी महत्वपूर्ण लगता है। आखिरकार, यह कहना आसान है कि दंगे और संपत्तियों का नुकसान बुरी बात है। इन बयानों से हर कोई सहमत है। हालांकि पूरे मुद्दे को इन कार्रवाइयों का समर्थन किया जाये अथवा न किया जाये की ओर मोड़ देने से विरोधों के बुनियादी कारण न्यून व उपेक्षित हो जाते हैं। सच तो यह है कि यह तर्कशीलता प्रदर्शनों के पीछे के कारणों को स्वीकार ही नहीं करती या चुनौती तक नहीं देती। यहीं पर डोनाल्ड ट्रम्प और उनके समर्थकों के तर्क चूक जाते हैं। नस्लीय असमानता और पुलिस अत्याचार का मुकाबला करने की बजाय ये नागरिक इतने असंतुष्ट हैं कि गुमराह होकर नकली पुतलों से लड़ रहे हैं। उपद्रव मचाते हुए ये नागरिक अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उनके साथ हुए अन्याय के रोष में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उससे वह लक्ष्य हासिल नहीं होता जिसमें असमानता और पुलिस अत्याचार पर कार्रवाई हो अथवा न्याय मिले। जनउद्रेक आखिरकार हवा से तो नहीं उपजता- जैसा कि कुछ अमेरिकी सोचते हैं। ट्रम्प का प्रतिसाद अमेरिका के दक्षिणपंथियों के विचारों के ही अनुरूप था, जिसमें दावा किया गया कि रिटेनहाऊस एक एनफोर्सर की तरह था जो जटिल परिस्थिति में फंस गया था। ट्रम्प कहते हैं-मुझे ऐसा लगता है कि वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वे यह भी कहते हैं-मेरा ख्याल है कि वह बहुत बड़े संकट में था। वह मारा जा सकता था। उपरोक्त आशय का बयान ऐसी परिस्थिति में तो अर्थपूर्ण हो सकता है जिसमें रिटेनहाऊस का मुकाबला भीड़ से हुआ था, पर दुर्भाग्य से केनोशा का मामला ऐसा नहीं था। याद रखें, रिटेनहाऊस ने हथियारों के साथ ऐसे समूह में हिंसा करने की मंशा के साथ राज्य की सीमाएं पार की थीं जिसका वह हिस्सा नहीं था। किसी भी अन्य स्थिति में उसे आतंकवादी ही समझा जायेगा।

अध्यादेशों पर क्यों नहीं हैं किसान आंदोलन

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने जून 2020 में कृषि से सम्बन्धित तीन अध्यादेश पारित किए थे-कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश-2020,श् श्किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं अध्यादेश-2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश-2020।श् ये तीनों ही अध्यादेश कोविड-19 जैसी अभूतपूर्व आपदा में जारी तालाबन्दी के दौरान लाए गए थे और संसद के मौजूदा मानसून सत्र में इन अध्यादेशों पर चर्चा होने और इन्हें कानून की शक्ल दिए जाने की उम्मीद है।

भारत में किसान अपने उत्पादों को कृषि उपज मंडी में लाइसेंसधारी व्यापारियों को ही बेच सकते हैं। देखा जा रहा है कि इन मण्डियों में व्यापारियों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती, नतीजतन किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। कानूनन किसान अपने उत्पाद को बाहर खुले में नहीं बेच सकते थे इसलिए मजबूरन वो मण्डी के व्यापारियों के मोहताज बन जाते थे। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश-2020 किसानों को आजादी देता है कि वे अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकें- वे सीधे खेत, खलिहान या फिर गोदामों और शीतगृहों से अपने उत्पाद बेच सकते हैं। वे अपना माल ले जाकर किसी कारखाने को भी बेच सकते हैं। किसान और व्यापारी अपने माल को अन्य राज्यों में भी ले जाकर बेच सकेंगे और व्यापारी खुद खेतों व गोदामों तक जाकर कृषि उत्पाद खरीद सकेंगे। यह अध्यादेश कृषि उपज की ऑनलाइन खरीदी-बिक्री को भी मान्यता देता है और राज्य सरकारों को किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफार्मो से किसी भी तरह के लेवी, मण्डी शुल्क या सेस लेने से भी रोकता है। केन्द्र सरकार ने दावा किया है कि यह किसानों, व्यापारियों और आम उपभोक्ता ओं को कृषि उत्पाद बेचने, खरीदने, भण्डारण और परिवहन करने जैसी आवश्यक गतिविधियों में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए व्यापक लोकहित में उठाए गए समीचीन कदम हैं। इसके जरिए किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, कृषि उपज मण्डी समितियोंश् का एकाधिकार खत्म होगा एवं व्यापारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे कृषि उत्पादों की खरीदी-बिक्री में कुशलता, पारदर्शिता और बाधा-रहित व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार के मुताबिक तीनों अध्यादेश किसान और व्यापारियों के हित में, उन्हें अपना माल खरीदने-बेचने की आजादी देते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार कृषि उत्पादों की स्वतंत्र खरीदी-बिक्री सुनिश्चित करने के लिए श्न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था भी खत्म करने जा रही है।

किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं अध्यादेश-2020श् के तहत किसान किसी व्यक्ति, सहकारी संस्था, कम्पनी आदि के साथ अपनी उपज को बेचने का अग्रिम करार, यानी फसल कटने से पहले ही उसे बेचने के लिए किया गया समझौता, कर सकते हैं। इस करार में उत्पाद की कीमत परस्पर सहमति से तय किए जाने की छूट है। करार के तहत किसान को मिलने वाली रकम, उसके द्वारा बैंक या किसी सरकारी योजना से लिए गए कर्ज से लिंक कर दी जाएगी। मतलब, उपज के दाम मिलने पर पहले कर्जा चुकाया जाएगा, बची हुई रकम किसान के खाते में आएगी। कृषि उत्पाद की खरीद-बिक्री को नियंत्रित करने वाले राज्य सरकारों के कानून इस करार पर लागू नहीं होंगे। आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश-2020 में भी जून 2020 में संशोधन किया गया है। इसके तहत अनाज, दालें, खाद्य तेल और चीनी को आवश्यक वस्तु के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यानी अब इनका असीमित संग्रहण, भण्डारण और परिवहन किया जा सकता है। जाहिर है कि ये तीनों अध्यादेश कृषि उपज को खुले बाजार के हवाले कर रहे हैं। किसान से अपेक्षा की जा रही है कि वह व्यापारियों, कम्पनियों, सहकारी समितियों से सौदेबाजी करके अपनी उपज का लाभप्रद मूल्य वसूल करे। आजादी के बाद से कृषि को मिले सरकारी संरक्षण का यह खात्मा है। कृषि उपज के दाम नियंत्रित करना दुधारी तलवार है। उपज के दाम कम हों तो किसान संकट में आ जाता है और अगर किसान को उपज का पूरा दाम दे दिया जाए, महंगाई अनियंत्रित हो सकती है। कृषि उत्पाद अन्य कई उद्योगों के लिए कच्चा माल होते हैं इसलिए आमतौर पर विश्व के अधिकांश मुल्कों की सरकारें अपने किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए, कृषि उपज के बाजार भाव को नियंत्रित करने के लिए, जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए विशिष्ट प्रावधान करती हैं। हम जानते हैं कि 1990 के दशक में विदर्भ, तेलंगाना और फिर पंजाब में किसानों की आत्महत्या की खबरों ने देश को झकोरना शुरु किया था। उसके बाद से किसानों के हालात बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन विरोध में कोई व्यापक आन्दोलन जमीन पर नजर नहीं आता। इस विडम्बना की पड़ताल की जानी चाहिए।

पहली बात तो यह कि किसान अपने आप में कोई एक समूह या वर्ग नहीं हैं। किसान जाति, जोत, वर्ग और राजनीतिक प्रतिबद्धता (यानी वोट बैंक) के रूप में न केवल बंटे हुए हैं, बल्कि परस्पर संघर्ष करते भी नजर आते हैं। इससे जुड़ा दूसरा पहलू किसानों की हैसियत का है। समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवासन का विश्लेषण बताता है कि 1960-70 के दशक में जो हरित क्रान्ति हुई थी, उसका लाभ देश के विभिन्न इलाकों में कुछ जातियों ने उठाया था। ये जाति समूह वर्ण-व्यवस्था में भले ही तथाकथित निचली और मध्यम पायदानों पर अवस्थित हों, लेकिन हरित क्रान्ति का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी न सिर्फ आर्थिक, बल्कि समाजिक और राजनैतिक हैसियत भी बढ़ाई और इसीलिए श्रीनिवासन इन्हें प्रभुत्वशाली जाति (डॉमिनेन्ट कास्ट) कहते हैं। इनके राजनीतिक-आर्थिक हित हाशिए के उन किसानों से बेहद अलग, कुछ अर्थो में प्रतिकूल हैं, जो कम जोत की खेती करते हैं, कृषि आधारित अन्य दस्तकारी करते हैं या फिर कृषि मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। देश में संसदीय और गैर-संसदीय दोनों तरह के राजनीतिक संगठन जब भी किसानों की बात करते हैं तब आमतौर पर वे किसानों के श्सोपानबद्धश् और परस्पर विरोधी समूहों में से किसी एक वर्ग की बात कर रहे होते हैं। परिणामस्वरूप किसानों की समस्याएं गम्भीर और व्यापक होते हुए भी देश के राजनीतिक पटल पर कोई गम्भीर और व्यापक श्किसान आन्दोलनश् नजर नहीं आता। इसके बाद, अगली समस्या नेतृत्व और उसकी समझ की है। आजाद भारत के इतिहास में किसान नेता के रूप में हम 5-7 नामों की गिनती कर सकते हैं, जिनका काम और असर अधिकांशतः किसी भौगोलिक क्षेत्र या सामाजिक वर्ग तक ही सीमित रहा है। किसान नेतृत्व ऐसा राष्ट्रीय स्वरूप नहीं ले सका है जिसके साथ तमाम इलाकों और वर्गों के किसान लामबन्द हो सकें। नेतृत्व से यहां यह आशय नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही हो, सामूहिक नेतृत्व की शक्ल में भी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। विविध क्षेत्रीय आन्दोलनों को जोड़ने और आपसी साझेदारी बनाने के प्रयासों की सीमा है। गणित के विपरीत राजनीति में भिन्न टुकड़ों को जोड़ने पर टुकड़ों का समूह बनता है, पूर्णांक नहीं बनता। इसलिए मसला किसान आन्दोलन की समझ का भी है। 1980 के दशक में देशभर में बड़े बांध, औद्योगिक मछलीपालन, विस्थापन आदि के खिलाफ और वनोपज पर जनजातियों के अधिकार जैसे जल-जंगल-जमीन के मुद्दों पर, मुद्दा आधारित क्षेत्रीय आन्दोलन चल रहे थे। ये तमाम आन्दोलन 1990 के दशक के अन्त तक धीरे-धीरे कमजोर होते गए और बीसवीं सदी के अन्त तक पर्यावरण और आमजन को इनसे जो हासिल होना था, वह हो चुका था। इसके बाद से ये आन्दोलन लगभग निष्प्रभावी हो गए हैं। किसानों की समस्या कोई मुद्दा नहीं है, ना ही किसान देश के किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में बसते हैं। किसान के हित की बात करते हुए व्यापारी और कृषि मजदूर के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसके साथ ही आम उपभोक्ता के सरोकारों का भी ध्यान रखना जरूरी है। इस रूप में कृषि की बात किसी एक वर्ग या क्षेत्र की बात न रहकर एक व्यापक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हाल में पेश हुए तीनों अध्यादेश कोई अकेली घटना नहीं है। एक बड़े एजेण्डे के तहत सरकारों के समाजवादी और लोक-कल्याणकारी स्वरूप को सीमित करके बाजार की पहुंच और असर को बढ़ाया जा रहा है। श्बहुपक्षीय व्यापार वार्ताश् के जरिए श्टटकर और व्यापार पर सामान्य समझौतेश् (जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड) तक पहुंचने के लिए उरुग्वे दौर की बातचीत (1986 से 1994), जिसमें भारत समेत 123 राष्ट्र शामिल थे, में यह एजेण्डा खुलकर सामने आया था। इस बातचीत की परिणति एक जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के रूप में हुई थी। इसमें कृषि उपज के साथ-साथ तमाम क्षेत्रों में सरकारी संरक्षणवाद को खत्म करके बाजार में बेलगाम वित्त के प्रवाह को खुली छूट देने की वकालत की गई थी। हम देख सकते हैं कि कृषि के साथ-साथ बैंक, खनन, भारी उद्योग, अधोसंरचना जैसे अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्रों के हितों की रक्षा करने वाले कानूनों में आमूल-चूल बदलाव करते हुए विदेशी पूंजी निवेश के लिए जगह बनाई गई। हाल के अध्यादेश भी उसी श्रृंखला का हिस्सा हैं। इसलिए इसे सिर्फ कृषि या मंडी के व्यापारियों की समस्या के रूप में एकांगी दृष्टिकोण से देखने के बदले देश की व्यापक अर्थनीति और संवैधानिक प्रावधानों पर आए एक तात्कालिक संकट के रूप में देखना होगा। तात्कालिक संकट की फौरी और पुरजोर प्रतिक्रिया जरूर होनी चाहिए, लेकिन यहीं तक सीमित रह जाना व्यापक लड़ाई को कमजोर करने वाला कदम हो सकता है। अर्थव्यवस्था और संवैधानिक मूल्य संकट में हैं। आजादी की लड़ाई जिन महान उद्देश्यों के लिए लड़ी गई, वो उद्देश्य भुलाए जा रहे हैं। आजादी के शुरुआती दशकों में नवनिर्माण के जिन सपनों को साकार करने के लिए लोगों ने खून-पसीना बहाया, उन सपनों को झुठलाया जा रहा है। समावेशी और प्रभावी आन्दोलन खड़ा करने के लिए हमें नेतृत्व, संगठन और लड़ाई के तौर-तरीकों पर नए सिरे से विचार करना होगा। इसकी राह तो आपसी संवाद और विमर्श से ही निकल सकती है, लेकिन इतना तय है कि मुद्दा आधारित और क्षेत्रीय आन्दोलनों का समय अब बीत चुका है।

सुधार पर आशंका

कृषि सुधारों की दिशा में केंद्र सरकार की पहल के बाद कोविड संकट के बीच किसान यदि सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनकी शंकाओं का समाधान किया जाना सरकार का दायित्व बनता है। निस्संदेह भारत में किसान राजनीतिक दलों का बड़ा वोट बैंक रहा है। सत्तारूढ़ दल भी इसका अपवाद नहीं है। पार्टी के घोषणापत्र में किसानों के तमाम मुद्दों के अलावा उनकी आय दुगनी करना भी रहा है। सवाल यह है कि आजादी के बाद किसानों की दूसरी आजादी की बात कहकर सरकार जो सुधार लागू करना चाहती है, उसको लेकर किसान आशंकित क्यों हैं। हम न भूलें कि भयावह कोरोना संकट के बीच यदि हम देश की बड़ी आबादी को मुफ्त अनाज दे पाये तो उसके पीछे किसानों की खून-पसीने की फसल ही थी, जिसने देश को संकटकाल में आत्मविश्वास दिलाया। वजह यह भी थी कि अन्न के भंडार सरकार के नियंत्रण में थे। पिछले दिनों आये जीडीपी के डरावने आंकड़ों के बीच यदि किसी क्षेत्र में सुधार देखा गया तो वह कृषि ही था। कुछ दिन पहले हरियाणा के किसान सरकार के तीन अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और पंजाब में भी धरनों का दौर जारी रहा। अब धीरे-धीरे आंदोलन उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में भी फैल गया। केवल गैर-भाजपाई राज्यों में ही नहीं, बल्कि भाजपा शासित राज्यों में भी किसान आंदोलनों की सुगबुगाहट तेज हुई है। गत पांच जून को लागू किये गये अध्यादेश और मौजूद संसद सत्र में पेश किये गये विधेयकों को लेकर किसानों के विरोध की वजह उन आशंकाओं को बताया जा रहा है, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि खेती में पूंजीपतियों-बिचौलियों का वर्चस्व हो जायेगा। वहीं सरकार का दावा है कि ये विधेयक किसान को आजादी देते हैं और उसकी प्रगति का रास्ता साफ करते हैं। इससे किसानों पर लगी कई बंदिशें हटेंगी और वह मनचाहे दामों पर अपनी उपज बेच सकेगा।

वहीं किसान संगठनों की चिंता है कि धीरे-धीरे किसान की उपज से न्यूनतम समर्थन मूल्य का कवच छीना जा रहा है। साथ ही मंडी समितियों से मिला संरक्षण भी खत्म हो जायेगा। इसलिये वे विधेयकों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को लेकर भी चिंताएं जतायी जा रही हैं कि किसान की भंडारण क्षमता न होने के कारण समृद्ध संसाधनों वाले लोग कालाबाजारी करने लगेंगे, जिससे किसान और उपभोक्ता के हितों पर कुठाराघात होगा। वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी आशंकाएं जतायी जा रही हैं कि इससे किसान अपने ही खेत में श्रमिक बन जायेगा। किसानों को आशंका है कि जो पूंजीपति ठेके पर कृषि उत्पाद खरीदेगा, उसे प्राकृतिक आपदा या अन्य तरीके से हुए नुकसान से कोई लेना-देना नहीं होगा, जिसका खमियाजा सिर्फ किसान को ही भुगतना होगा। किसान इस बात से भी आशंकित हैं कि कहीं भी उत्पाद बेचने की आजादी के साथ सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को खत्म कर सकती है। किसानों की मांग है कि विधेयक में किसान को एमएसपी की गारंटी देने के स्पष्ट प्रावधान लाये जायें। जानकारों का मानना है कि सरकार विकसित देशों की तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करना चाहती है, जिसके परिणाम किसानों के हितों में नहीं रहे हैं। इसके अलावा भारत में कृषि की छोटी जोतों के चलते खेती व्यापार का नहीं, जीवनयापन का जरिया है। साथ ही अतीत के अनुभव बताते हैं कि सूखे और अकाल की स्थिति में लोग अन्न की कमी के नहीं, बल्कि उसकी कालाबाजारी का शिकार होते हैं। निस्संदेह आवश्यक वस्तु अधिनियम को बदलने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद सरकार का दखल अनाज भंडारण में खत्म हो जायेगा जो देश के गरीब लोगों के हित में भी नहीं है। इन बदलावों को लेकर देशव्यापी बहस होनी चाहिए। वैसे भी कृषि राज्यों का विषय है। संवैधानिक रूप से भी केंद्र को किसानों को प्रभावित करने वाले कानून की दिशा में आगे बढ़ने से पहले राज्यों से परामर्श करना चाहिएथ्था। जल्दबाजी में विधिवत प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया है।

सार समाचार .....

आईपीएल के 13वें सीजन में स्टेडियम में मीडिया की नो एंट्री

नई दिल्ली **एजेंसी।**

आईपीएल के 13वें सीजन में बीसीसीआई ने स्टेडियम में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। बीसीसीआई ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए लगाए गए सख्त स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में मीडिया को स्टेडियम में जाने की इजाजत नहीं होगी। शुक्रवार देर शाम बीसीसीआई गाइडलाइन जारी की है। आईपीएल का पहला मैच शनिवार को शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा।

यह पहला सीजन होगा, जिसमें फ्रेंचाइजी को मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस कराने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि हर मैच के बाद वर्चुअल मीडिया कांफ्रेंस कराना जरूरी होगा।

स्टेडियम में नो एंट्री

बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा, 'ड्रीम11 इंडियन प्रीमियर लीग 2020 कोविड-19 महामारी के कारण यूएई में बंद स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल को देखते हुए मीडिया कर्मियों को मैच कवर करने के लिए या टीम के अभ्यास सत्र को कवर करने के लिए स्टेडियम में अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी

इटालियन ओपनज क्वार्टरफाइनल में टूटी बोपन्ना और शापोवालोव की चुनौती

बेंगलुरू एजेंसी। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार कनाडा के डेनिस शापोवालोव को शुक्रवार को कड़े संघर्ष में क्वार्टरफाइनल में हारकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो जाना पड़ा। बोपन्ना और शापोवालोव की गैर वरीय जोड़ी को फ्रांसीसी जोड़ी जेरेमी चार्डी और फेब्रिस मार्टिन ने एक घंटे 32 मिनट में 4-6, 7-5, 10-7 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय और कनाडाई जोड़ी ने पिछले राउंड में शीर्ष वरीयता शीर्ष वरीयता प्राप्त कोलंबिया की जोड़ी जुआन सेबेस्टियन कबाल और रॉबर्ट फराह को 6-3, 3-6, 10-5 से हराया था, लेकिन अंतिम आठ में वे अपनी चुनौती गंवा बैठे।

बोपन्ना और शापोवालोव पिछले सप्ताह समाप्त हुए वर्ष के आखिरी ग्रैंड स्लेम यूएस ओपन के क्वार्टरफाइनल तक पहुंचे थे और इटालियन ओपन में भी उनका सफर क्वार्टरफाइनल में ही थम गया। भारतीय और कनाडाई खिलाड़ी की जोड़ी ने पहला सेट 6-4 से जीत लिया, लेकिन दूसरा सेट 5-7 से गंवा बैठे। सुपर टाई ब्रेक में बोपन्ना और शापोवालोव को 7-10 से हार का सामना करना पड़ा।'

आस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली का दावा, मलिंगा की कमी नहीं खलने देंगे जसप्रीत बुमराह

दुबई एजेंसी।

आस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली का मानना है कि शनिवार से शुरू हो रहे आईपीएल के आगामी सीजन में जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस को श्रीलंका के दिग्गज लसिथ मलिंगा की कमी नहीं खलने देंगे। मलिंगा ने निजी कारणों से इस साल आईपीएल से नाम वापस ले लिया है। ली मानते हैं कि बुमराह नई और पुरानी गेंद के साथ चमत्कार कर सकते हैं और यही कारण है कि वह मलिंगा की कमी नहीं खलने देंगे। ब्रेट ली ने कहा, जब से बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं, तब से मैं उनका फैन हूं। उनका एक्शन अलग है और इसी कारण वह गेंद को दोनों तरफ से स्विंग करा सकते हैं। वह नई और पुरानी गेंद के साथ असरदार हैं और निश्चित तौर पर वह डेथ ओवर्स में मुंबई इंडियंस को मलिंगा की कमी नहीं खलने देंगे।

सीएसके खिताब की प्रबल दावेदार

आस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को खिताब का दावेदार करार देते हुए कहा कि स्पिन विभाग में विविधता से टीम को यूएई की परिस्थितियों में फायदा होगा। ब्रेट ली ने कहा, सीएसके काफी मजबूत टीम है। मैंने उनकी स्पिन आक्रमण के कारण उनके चैंपियन बनने का अनुमान लगाया है। ब्रेट ली ने कहा टीम में मिशेल सेंटनर के होने के कारण जडेजा को अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा, ताकि वे टीम के शीर्ष स्पिनर बने रहे।

मुंबई और चेन्नई चौथी बार ओपनिंग मैच में आमने-सामने

दोनों टीमों के बीच अब तक हुए तीन ओपनिंग मैच में से 2 मुंबई इंडियंस और 1 सीएसके जीती है। आईपीएल का फाइनल दीपावली से 4 दिन पहले यानि 10 नवंबर को खेला जाएगा। इस दौरान 53 दिन में 8 टीमें 14-14 मैच खेलेंगी। टूर्नामेंट में एक एलिमिनेटर, 2 क्वालिफायर और फाइनल समेत 60 मैच होंगे। यह सभी मुकाबले दुबई (24), अबु धाबी (20) और शारजाह (12) में होंगे।

एजेंसी।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन की आज से यूएई में शुरुआत होगी। पहला मैच डिफेंडिंग चैम्पियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच अबु धाबी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के इतिहास में यह चौथी बार है, जब दोनों टीमें ओपनिंग मैच खेलेंगी। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए तीन ओपनिंग मैच में से 2 मुंबई इंडियंस और 1 सीएसके जीती है।

आईपीएल का फाइनल दीपावली से 4 दिन पहले यानि 10 नवंबर को खेला जाएगा। इस दौरान 53 दिन में 8 टीमें 14-14 मैच खेलेंगी। टूर्नामेंट में एक एलिमिनेटर, 2 क्वालिफायर और फाइनल समेत 60 मैच होंगे। यह सभी मुकाबले दुबई (24), अबु धाबी (20) और शारजाह (12) में होंगे।

यूएई में मुंबई का खराब रिकॉर्ड

डिफेंडिंग चैम्पियन मुंबई ने पिछले सीजन के फाइनल में सीएसके को 1 रन से शिकस्त दी थी। इस बार टीम फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत से आगाज करना चाहेगी। वैसे यूएई में मुंबई का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। लोकसभा चुनाव के कारण 2014 में आईपीएल के शुरुआती 20 मैच यूएई में हुए थे। तब मुंबई ने यहां 5 मैच खेले और सभी में उसे हार मिली थी।

चेन्नई ने यूएई में 6 में से 5 मैच जीते

सीएसके ने 6 साल पहले यूएई में 5 मैच खेले थे। टीम को 4 में जीत मिली और 1 मैच हारी थी। अबु धाबी में सीएसके ने 2 मैच खेले थे, जिनमें से एक में जीत और एक में शिकस्त मिली थी। वहीं, मुंबई इंडियंस ने इस मैदान पर एक ही मैच खेला, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 41 रन से हराया था।

2018 में हुए ओपनिंग मैच में चेन्नई ने मुंबई को हराया था

इस मैच में उतरने के साथ ही मुंबई सबसे ज्यादा 7 बार आईपीएल का ओपनिंग मैच खेलने वाली टीम बनेगी। उसने अब तक 6 ओपनिंग मैच खेले हैं, जबकि कोलकाता नाइटराइडर्स ने भी इतनी ही बार पहला मैच खेला है। मुंबई-चेन्नई के बीच आईपीएल का पिछला ओपनिंग मैच 2018 में हुआ था। तब चेन्नई सुपरकिंग्स रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से जीती थी।

12 में से 7 खिताब मुंबई और चेन्नई ने ही जीते

अब तक हुए 12 सीजन में से मुंबई और चेन्नई ने 7 बार खिताब जीते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मुंबई 4 और सीएसके 3 बार चैम्पियन रही है। सभी खिताब सीएसके ने महेंद्र सिंह धोनी और मुंबई ने रोहित शर्मा की कप्तानी में ही जीते हैं।

हेड-टु-हेड

दोनों टीमों के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें मुंबई ने सबसे ज्यादा 18 और चेन्नई ने 12 मुकाबले जीते हैं। इनमें दो मुकाबले चैम्पियंस लीग टी-20 के भी शामिल हैं। पिच और मौसम रिपोर्ट- अबु धाबी में मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा। तापमान 29 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिच से बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है। यहां स्लो विकेट होने के कारण स्पिनर्स को भी काफी मदद मिलेगी। शेख जाएद स्टेडियम में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। यहां हुए पिछले 44 टी-20 में पहले गेंदबाजी वाली टीम की जीत का सक्सेस रेट 56.8त्न रहा है।

इस मैदान पर हुए कुल टी-20- 44

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती- 19

पहल गदबाजा करन वाला टाम जाता- 25

पहली पारी में टीम का औसत स्कोर- 137

दूसरी पारी में टीम का औसत स्कोर- 128

इस सीजन में रैना-हरभजन के बिना उतरेगी चेन्नई

इस बार धोनी की सीएसके टीम अपने टॉप स्कोरर सुरेश रैना और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हरभजन सिंह के बगैर उतरेगी। इस महीने की शुरुआत में सीएसके के दो प्लेयर दीपक चाहर और रितुराज गायकवाड़ समेत 13 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे। रितुराज को छोड़कर सभी ठीक हो चुके हैं। इस मामले के बाद रैना टूर्नामेंट छोड़कर देश लौट गए, जबकि हरभजन यूएई आए ही नहीं और नाम वापस ले लिया। रैना ने अब तक 193 मैच में 5368 रन बनाए हैं। वे विराट कोहली (5412) के बाद दूसरे टॉप स्कोरर हैं। वहीं, हरभजन सिंह टीम के टॉप विकेट टेकर हैं। उन्होंने अब तक 160 मैच में 150 विकेट लिए हैं।

मुंबई इंडियंस में मलिंगा की कमी बुमराह पूरी करते नजर आएंगे

श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने 122 मैच में सबसे ज्यादा 170 विकेट लेकर टॉप पर काबिज हैं। हालांकि, वे कोरोना के कारण पहले ही टूर्नामेंट से हट चुके हैं। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा को जसप्रीत बुमराह से पूरी उम्मीद है कि वे मलिंगा की कमी को पूरा करेंगे। बुमराह ने 77 मैच में 82 विकेट लिए हैं।

इस मैच में धोनी-रोहित सबसे मंहगे खिलाड़ी रहेंगे

इस मुकाबले में दोनों टीम की ओर से धोनी और रोहित ही सबसे मंहगे खिलाड़ी रहेंगे। दोनों को अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी

152 रन देने के बाद भी विराट कोहली को आउट नहीं कर पाए हैं अश्विन

नई दिल्ली | एजेंसी।

आईपीएल 2020 की शुरुआत मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के मैच से हो रही है। अभी तक 12 सीजन में कई अनोखे रिकॉर्ड बने हैं। सबसे सफल गेंदबाजों में से एक रविचंद्रन अश्विन बेंगलुद्धरु के कप्तान विराट कोहली को आउट नहीं कर पाए हैं। विराट ने उनकी गेंदबाजी पर 152 रन बनाए हैं। इसी तरह से कई और रिकॉर्ड हैं।

धोनी ने अपने 49.79त्न रन अंतिम चार ओवरों में बनाए हैं जो 2206 रन हैं।

शिखर धवन ने हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में 1378 रन बनाए हैं। किसी बल्लेबाज की ओर एक मैदान पर बिना जीरो पर आउट हुए सबसे ज्यादा रन। धोनी ने करिअर के 22त्न छक्के (46) 20वें ओवर में लगाए हैं।

क्रिस सिल्वरवुड बोले, बस खिलाड़ियों के चोटिल होने का डर

मैनचेस्टर , एजेंसी। इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड को यकीन है कि आईपीएल जैसे विश्व स्तरीय टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को टी-20 विश्व कप की तैयारी में मदद मिलेगी। पर उन्हें खिलाड़ियों की थकान और चोटिल होने का डर है। इंग्लैंड के दस क्रिकेटर आईपीएल खेलने यूएई पहुंच गए हैं। इनमें से सात क्रिकेटर हाल ही में आस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में इंग्लैंड टीम का हिस्सा थे।

सिल्वरवुड ने कहा कि खिलाड़ियों को बर्न आउट से बचने के लिए एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि अगले सात हफ्ते वे बायो बबल में रहेंगे। यह उनका फैसला है, लेकिन हमें उन पर नजर रखनी होगी। अनुबंध बहुत लुभावने हैं, लेकिन हमें टी-20 विश्व कप की भी तैयारी करनी है। जितना ज्यादा टी-20 क्रिकेट खेलेंगे, हमारे लिए अच्छा ही होगा। टी-20 विश्व कप भारत में अगले साल अक्तूबर-नवंबर में होगा। इंग्लैंड के जोस बटलर, टॉम कुरेन और जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, जबकि सीमित ओवरों के कप्तान इयोन मॉर्गन और टॉम बेंटन कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में हैं।

लोरेंजो मुसेटी का स्वप्निल अभियान जारी, इटालियन ओपन में केई निशिकोरी को दी मात

मैनचेस्टर , एजेंसी। इटली के युवा खिलाड़ी लोरेंजो मुसेटी का रोम में चल रहे इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्वप्निल अभियान जारी है। उन्होंने एटीपी टूअर में अपने दूसरे मैच में ही जापान के अनुभवी खिलाड़ी केई निशिकोरी को लगातार सेटों में 6-3, 6-4 से मात देकर तीसरे दौर में जगह बना ली। 18 वर्षीय मुसेटी ने इससे पहले तीन बार के ग्रैंड स्लेम चैंपियन और विश्व के पूर्व नंबर तीन खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के स्टेनिस्लास वावरिंका को लगातार सेटों में हराया था। मुसेटी ने इस तरह टॉप पांच के दो पूर्व खिलाड़ियों को लगातार मैचों में शिकस्त दे दी है।

उन्होंने अपने शानदार अभियान को लेकर कहा, मैं हमेशा एक योद्धा और एक लड़ाकू खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन पिछले वर्ष के दौरान मैंने बहुत उतार-चढ़ाव देखे। उन्होंने कहा, इस महीने मैंने खुद को शांत रखने का प्रयास किया और मैदान पर सकारात्मक रहने की कोशिश की।

टेनिस स्टार गेल मोनफिल्स इटैलियन ओपन में हारे फैन्स ने उन्हें वेबकूफ और बंधुआ तक कह दिया

नई दिल्ली , (जी.एन.एस)

फ्रांस के टेनिस स्टार गेल मोनफिल्स को इटैलियन ओपन में हार के बाद फैन्स के गुस्से का सामना पड़ा। उन्हें डोमिनिक कोएफर ने 6-2, 6-4 से हराया था। गेल मोनफिल्स ने कहा कि इटैलियन ओपन मे हारने के बाद उन पर फैन्स ने नस्लीय टिप्पणी की। इंस्टग्राम पर एक फैन्स ने उन्हें बेवकूफ और बंधुआ कहा। मोनफिल्स ने कहा- मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन, मैं कामयाब नहीं रहा। इसके अलावा जो कुछ हुआ वो भी ठीक नहीं था। गेल का इशारा फैन्स के कमेंट्स की तरफ था।

इटैलियन ओपन 27 सितंबर से चल रहा है। यह फ्रेंच ओपन से पहले खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस टूर्नामेंट है।

फैन्स ने कहा-आप टॉप टेन में रहने के योग्य नहीं

एक अन्य फैन ने मोनफिल्स के हार के बाद कहा कि आप टॉप टेन में रहने के योग्य नहीं है। मोनफिल्स का भी वर्तमान वर्ल्ड रैंकिंग 9 है। वे 2016 में अपने करियर के बेस्ट रैंकिंग 6 पर थे। उन्होंने अपने करियर में 10 टाइटल भी जीते हैं।

तंज का सिलसिला पुराना

ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी डोमिनिक थिएम को पिछले साल चैलेंजर टूर में फैन्स के टिप्पणी का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा था, चैलेंजर टूर के पहले मैच से मुझे बहुत ही खराब टिप्पणी मिल रही है। लेकिन मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। आपको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। केविड एंडरसन को भी इस तरह की गलत बातों का सामना करना पड़ा है। साल 2016 में उन्होंने कहा था कि विंबलडन में पहले दौर में ही हार का सामना करने पर मौत की धमकी मिल रही है।

वुमन्स सिंगल्स में सिमोना और डायना अंतिम आठ में पहुंचीं

नोवाक जोकोविच ने सर्बिया के ही फिलिप क्राजिनोविच को सीधे सेटों में मात दी। टॉप 16 के अन्य मैचों में स्पेन के नडाल ने सर्बिया के दुसान लोजोविच को, इटली के माटेयो बारेटिनी ने इटली के ही स्टीफानो ट्वागिला को और जर्मनी के डोमिनिक कोएपफेर ने इटली के लोरेंजो मुसेटी को हराया।

दिल्ली | एजेंसी।

इटैलियन ओपन में शुक्रवार को खेले गए अंतिम 16 के मैचों में सर्बिया के नोवाक जोकोविच, स्पेन के राफेल नडाल, इटली के माटेयो बारेटिनी और जर्मनी के डोमिनिक कोएपफेर ने जीत कर मेंस सिंगल्स के क्वाटर फाइनल में जगह बना ली। महिला वर्ग में रोमानिया की सिमोना हालेप, स्पेन की गार्बिने मुगुरुराज, चेक रिपब्लिक की कैरोलीना प्लिसकोवा और बेलारूस की विक्टोरिया एजारेंका क्वॉर्टर फाइनल में पहुंच गईं।

वुमन्स सिंगल्स में रोमानिया की सिमोना हालेप ने यूक्रेन की डायना यास्ट्रेमस्का को और स्पेन की गार्बिने मुगुरुराज ने ब्रिटेन की योहाना कोंटा को मात दी। जबकि बेलारूस की विक्टोरिया एजारेंका वॉकओवर मिल जाने से क्वाटर फाइनल में पहुंच गईं।

मेंस सिंगल्स के सभी मैचों का फैसला सीधे सेटों में हुआ

सर्बिया के जोकोविच ने शुक्रवार को अपने ही देश के फिलिप क्राजिनोविच को सीधे सेटों में 7-6 (7), 6-3 से हरा कर लगातार 14वीं बार इस टूर्नामेंट के टॉप-8 में जगह बनाई। जोकोविच ने कहा, यह निश्चित तौर पर मेरे द्वारा खेला गया अभी तक के सबसे लंबे सेट्स में से एक है। मुझे लगता है कि जो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो उसके खिलाफ खेलना कभी भी आसान नहीं होता है। मुझे लगता है कि पहला सेट अलग जा सकता था। वर्ल्ड नंबर-1 खिलाड़ी ने कहा, किस्मत की बात है कि यह मेरे पक्ष में गया और इससे मुझे दूसरे सेट में मदद मिली। हो सकता है कि मानसिक और शारीरिक तौर पर वह कुछ पीछे रहे गए हों और मैंने मौकों को फायदा उठा लिया।

वहीं अंतिम-16 के एक अन्य मैच में नौ बार के विजेता नडाल ने डुसान लोजोविच को 6-1, 6-3 से हरा दिया।

नडाल ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने काफी सकारात्मक टेनिस खेली है। जाहिर सी बात है कि सुधार लगातार होना चाहिए। मेरे लिए यह एक और शानदार शाम रही ।

स्टान वावरिंका और जापान के केई निशिकोरी को मात देने वाले इटली के लोरेंजो मुसेटी को जर्मनी के डोमिनिक कोएपफेर ने 6-4, 6-0 से हरा दिया। चौथे सीड इटली के माटेयो बारेटिनी ने इटली के ही स्टीफानो ट्वागिला ने 7-6 (5), 7-6 (1) को हरा कर टॉप-8 में जगह बनाई।

पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 को वॉकओवर

महिला वर्ग में रोमानिया की सिमोना हालेप ने यूक्रेन की डायना यास्ट्रेमस्का को 7-5, 6-4 से हरा दिया। दूसरी सीड कैरोलीना प्लिस्कोवा ने रूस की एना ब्लिनकोवा को 6-4, 6-3 से मात दी। स्पेन की गार्बिने मुगुरुराज ने ग्रेट ब्रिटेन की योहाना कोंटा को 6-4, 6-1 से हरा दिया। पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 विक्टोरिया एजारेंका की विपक्षी खिलाड़ी रूस की डारया कासाटकिना के पहले सेट में रिटायर होने से उन्हें वॉकओवर मिल गया और वे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं।

बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड विली ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी

नई दिल्ली | एजेंसी।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर डेविड विली को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डेविड विली की वाइफ भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। गुरुवार को खुद डेविड विली ने इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी कि वे और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डेविड विली मौजूदा समय में इंग्लैंड में खेली जा रही टी20 लीग टी20 ब्लास्ट में खेल रहे थे।

डेविड विली ने क्या कहा

बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड विली ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सभी तरह के संदेशों के लिए धन्यवाद। मेरी पत्नी और मुझे कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। बचे हुए मैचों को मिस करने पर दुख हो रहा है। इससे भी अधिक दुखी करने वाली स्थिति यह है कि मैं 3 अन्य खिलाड़ियों के संपर्क में आ गया (इससे पहले कि हमारे लक्षण थे) था, इसका अर्थ है कि वे जोखिम में हैं और उपलब्ध भी नहीं हैं।अबतक का प्रदर्शन शानदार रहा 30 वर्षीय डेविड विली आखिरी बार पिछले महीने आयरलैंड के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में इंग्लैंड की टीम के लिए खेले थे।

उन्होंने अपने करियर में अब तक 49 वनडे और 28 टी20 इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड के लिए खेले हैं। वहीं, घरेलू क्रिकेट में उनका करियर लंबा रहा है और वे अब तक 71 फर्स्ट क्लास मैच और 132 लिस्ट ए मैच अलग-अलग टीमों के लिए खेल चुके हैं। विली ने वनडे क्रिकेट में 60 और टी20 क्रिकेट में 34 विकेट चटकाए हैं। इससे पहले यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब ने घोषणा की कि डेविड विली, टॉम कोहलर-कैडमोर, जोश पोयसडेन और मैथ्यू फिशर अपने शेष विटालिटी ब्लास्ट ग्रुप मौचों को मिस करेंगे।

ग्रीन खान के इंस्टाग्राम पर हुए 9 मिलियन फॉलोअर्स

बॉलिवुड ऐक्ट्रेस जरीन खान फिल्मों से भले ही दूरी बनाए हों लेकिन सोशल मीडिया पर ऐक्टिव रहती हैं। वह आए दिन अपने फोटोज और वीडियोज फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। वहीं जरीन खान के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 90 लाख यानी 9 मीलियन पार हो चुकी है। इस खुशी को ऐक्ट्रेस ने अलग अंदाज में मनाया है। जरीन खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह पेरिस की सड़क पर डांस करते नजर आ रही हैं। इस वीडियो को 5 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। जरीन खान ने अपनी इस पोस्ट के साथ लिखाए अपने 9 मिलियन इंस्टा फैमिली का जश्न मना रही हूं। आप सभी के प्यार का धन्यवाद। इसे ऐसे ही बनाए रखें। कोरोना वायरस के चलते फिल्म इंडस्ट्री में काम रुक गया था। जरीन खान ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वह अपने घर में कमाने वाली एकमात्र सदस्य हैं। वह पिछले कुछ महीनों से वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रही थीं। जरीन खान ने कहा था कि वह जल्द से जल्द काम शुरू करने की उम्मीद कर रही थीं। ऐक्ट्रेस को लेकर ऐसी भी खबरें थी कि वह बिग बॉस 14 में भाग ले रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कई वर्षों से शो के लिए संपर्क किए जाने के बावजूद वह इसमें भाग नहीं ले रही थीं। जरीन खान के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2010 में आई फिल्म वीर से बॉलिवुड डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 1921ए रेडीए हाउसफुल 2 हेट स्टोरी 3 अक्सर 2 जैसी फिल्मों में काम किया है। बॉलिवुड के अलावा जरीन खान ने तेलुगू और पंजाबी सिनेमा में भी किया है।

यश माता.पिता को मानते हैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि

भारतीय स्टार यश ने स्टारडम को हासिल करने के लिए अपना दिल और आत्मा लगा दिया। यश बड़ी विनम्रता से यह कहते हैं कि माता.पिता का आशीर्वाद खुशी और उनकी आंखों में गर्व उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। यश के लिए उनका परिवार और उनके माता.पिता का अर्थ ही उनके लिए दुनिया है। वह जो भी मेहनत करते हैं उसे उनके माता पिता गर्वान्वित महसूस करें। यश निश्चित रूप से अपने सपने को जी रहे हैं। जो उन्हें नहीं जानते उनके लिए यश बहुत विनम्र पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता बस कंडक्टर हुआ करते थे और उनकी मां एक गृहिणी थीं। दोनों ने घर की जरूरतों को पूरा करने और अपने बच्चों की चाह और इच्छाओं का पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। कभी.कभी खुद की जरूरतों को भी अनदेखा कर दिया था। इस तरह की कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ते हुए यश हमेशा अपने माता.पिता के लिए उन्हें आसान और आरामदायक जीवन प्रदान करने के लिए जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए दृढ़ हैं। वह उनके सभी सपनों को साकार करना चाहते हैं। अभिनेता से जुड़े एक करीबी ने कहा यश इस पीढ़ी के सेल्फमेड मैन का सबसे अच्छा उदाहरण है। कोई जो अपने हाथ में कुछ भी नहीं के साथ शुरू करता है वह धीरे.धीरे और नियमितता से अपना साम्राज्य खड़ा करता हैं ईंट से ईंट सरासर दृढ़ संकल्प लिए जुनून और ईमानदारी के साथ। उनके माता.पिता को हमेशा न केवल उनकी उपलब्धियों पर गर्व रहा है बल्कि उन्होंने हर कदम पर जिस तरह चुनौतियों को पार किया और एक व्यक्ति के रूप में विकसित हुए उसपर। धीरे.धीरे शुरू करते हुए अपने परिश्रम लगन और उपलब्धि को हासिल करने के साथ यश एक मुकाम पर पहुंट गये और अब एक व्यापक रूप से पैन इंडिया अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। और अब सुपरस्टार केजीएफ की अपनी बहुप्रतीक्षित अगली कड़ी के लिए और रॉकी भाई के रूप में बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हो रहे हैं।

श्रद्धा आर्या ने नेहा कक्कड़ के पंजाबी गाने पर किया मजेदार डांस

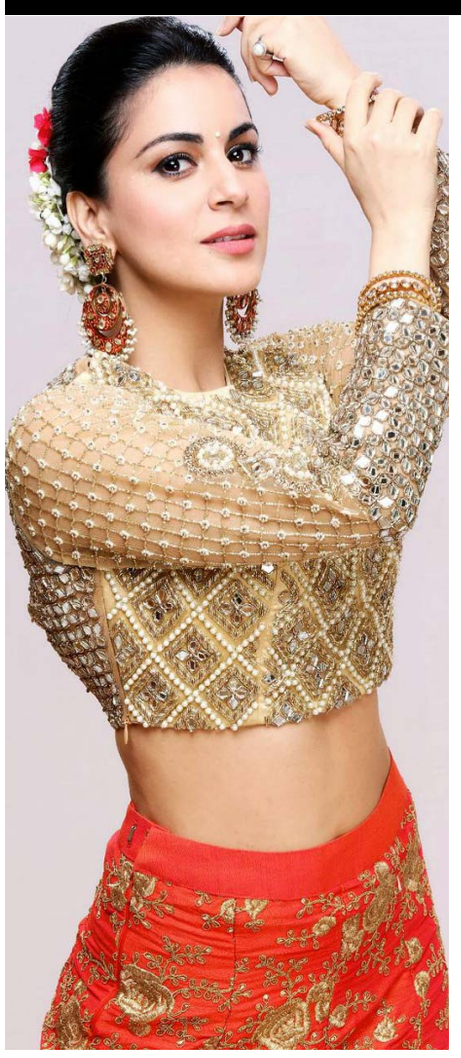

कुंडली भाग्य की लीड ऐक्ट्रेस प्रीता यानी श्रद्धा आर्या वीकेंड को लेकर बेहद खुश नजर आ रही हैं और अपनी यह खुशी उन्होंने एक डांस वीडियो शेयर कर दिखा भी दिया है। श्रद्धा ने अपना मजेदार डांस वीडियो शेयर किया हैए जिसमें उनके साथ नजर आ रही हैं उनकी फ्रेंड हिना परमार। श्रद्धा आर्या और हिना दोनों डेनिम लुक में नजर आ रही हैं। दोनों नेहा कक्कड़ के पंजाबी गाने पर झूमती दिख रही हैं। श्रद्धा आर्या ने इस डांस वीडियो को शेयर करते हुए वीकेंड की खुशी भी जाहिर की है। प्रीता का यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहाए जो रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा के गाने पिया पिया ओ पिया पिया की याद दिला रहा है। बता दें कि श्रद्धा आर्या को डांस करना काफी पसंद है और वह कभी भी डांस करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देतीं। जन्माष्टमी के मौके पर भी श्रद्धा ने मैया यशोदा पर बेहद खूबसूरत डांस किया था और फैन्स का दिल जीत लिया था। श्रद्धा इंस्टाग्राम पर काफी ऐक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें और मजेदार वीडियोज़ शेयर किया करती हैं। श्रद्धा की ये वकेशन की तस्वीरें लाजवाब हैं। श्रद्धा अक्सर अपने वकेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डाला करती हैं। श्रद्धा आर्या ने कुंडली भाग्य से पहले कई टीवी शोज किएए लेकिन इस शो ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। आज हर कोई श्रद्धा को असली नाम से कम और प्रीता के नाम से ज्यादा जानता है।

इंडस्ट्री वाले पार्टी में बुलाकर ट्रे पर ड्रग्स ऑफर करते हैं शर्लिन चोपड़ा

बॉलिवुड ऐक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग ऐंगल सामने आने के बाद एनसीबी की टीम जांच कर रही है और टीम ने रिया चक्रवर्ती सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद आई रिपोर्ट्स के मुताबिकए रिया ने ड्रग्स मामले को लेकर बॉलिवुड की कई बड़ी हस्तियों का नाम लिया है और कुछ नामों का खुलासा भी हुआ है। इसी बीच ऐक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने कहा है कि पार्टी में बुलाकर ड्रग ऑफर किया जाता है। शर्लिन चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह योग करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में शर्लिन चोपड़ा कहती हैंए आप लोग हमेशा मेरी फिटनेस का सीक्रेट पूछते हैंए तो सीक्रेट है न्यूट्रिशनए अनुशासन और योगा। योगा से होगाए अवश्य होगा।

शर्लिन चोपड़ा ने अपनी इस पोस्ट के साथ लिखाए मैं चेन स्मोकर थीए अक्टूबर 2017 में मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। ड्रग्स से मैंने हमेशा दूरी बनाई रखी है। इंडस्ट्री वाले पार्टी में बुलाकर ट्रे पर ड्रग्स ऑफर करते हैंए मगर लेने का नहीं। शर्लिन चोपड़ा कास्टिंग काउच को लेकर खुलासा करके भी चर्चा में आ चुकी हैं। शर्लिन चोपड़ा ने बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल होता है। ऐक्ट्रेस ने बताया कि शुरुआत में जब मैं निर्माताओं को काम के लिए अप्रोच करती थीए अपना परिचय देती थी तो वह मुझे डिनर पर बुलाते थे। तब मुझे इस बात आइडिया नहीं था। बाद में समझ आया कि डिनर का मतलब क्या होता है। इसके बाद कोई मुझे डिनर कोड वर्ड के साथ कुछ कहता था तो मैं कहती थी डिनर नहीं करतीं हूं। मेरी डाइट चल रही है।

जैकलीन ने लीडिंग मैगजीन के कवर पर बिखेरा जादू

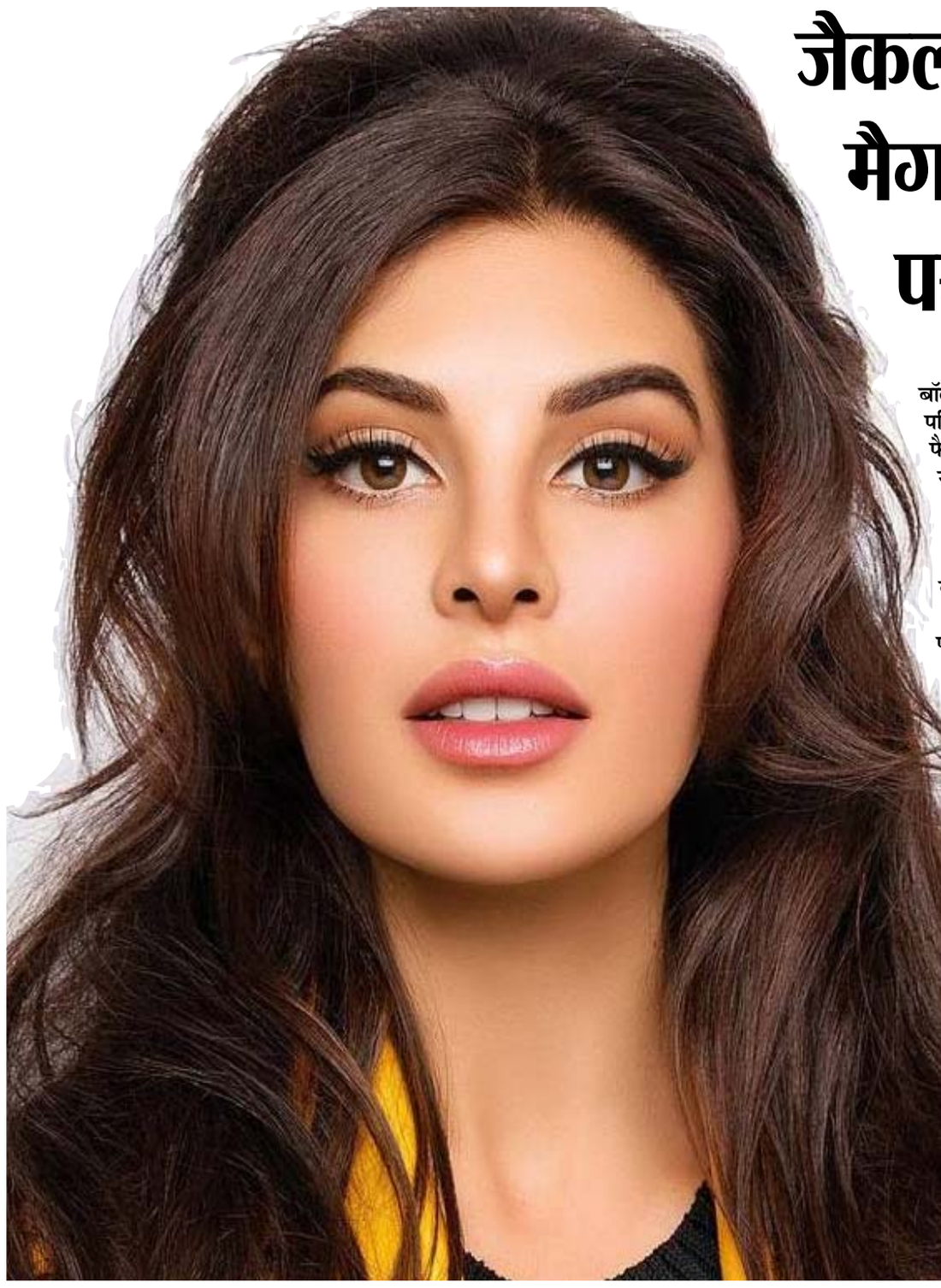

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने एक प्रमुख पत्रिका के कवर पर एक बार फिर से सकारात्मकता फैलाई। बॉलीवुड की मिस सनशाइन कवर पर बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आ रही है। जैकलीन को इस तस्वीर में कैमो प्रिंट जंपसूट पहने हुए देखा जाता हैए जिसकी पैंट के किनारे पर छोटी.छोटी जिप लगी हुई है और उनके पूरे सूट पर ब्लैक पैच वर्क देखा जा सकता है। अभिनेत्री ने सोने की चेन और न्यूट्रल मेकअप के साथ अपने इस लुक को पूरा किया है। मैगजीन ने अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा एक शाश्वत आशावादी जैकलीन फर्नांडीज की धूप की भावना संक्रामक हैए भले ही यह एक फोन कॉल के माध्यम से हो। एक प्रतिभाशाली एक्टर इस बारे में बात करता है कि वह अनिश्चितता के इस दौर को कैसे नेविगेट करना है क्योंकि वह अपनी खुद की सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक को मैप करता है। जैकलीन 2020 में बैक टू बैक सॉन्ग रिलीज के साथ सफलता का आनंद ले रही हैं और हाल ही में उन्होंने किक 2 और भूत पुलिस की भी घोषणा की है। अभिनेत्री ने पॉडकास्ट के लिए अमांडा सेर्नी के साथ भी हाथ मिलाया है और वह एक्शन अगेंस्ट हंगर फाउंडेशन के साथ साझेदारी कर रही हैं।

गौहर- जैद के रिश्ते को मिली परिवार की मंजूरी

बिग बॉस विनर गौहर खान इन दिनों डांस कोरियोग्राफर जैद दरबार से बढ़ती नजदीकियों के चलते चर्चा में हैं। दोनों इन दिनों ज्यादा समय साथ बिताते हैं जिसके गवाह उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैं। एक लंबे समय तक रिश्ते को प्राइवेट रखने के बाद अब जैद ने आगे बढ़ते हुए परिवार वालों को भी इसकी जानकारी दी है। जैद, म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार की पहली पत्नी फरजाना के बेटे हैं लेकिन उनकी मौजूदा पत्नी आएशा के भी बेहद करीब हैं ऐसे में जब उन्होंने गौहर से रिश्ते की बात सामने रखी तो दोनों ने ही उन्हें मंजूरी दे दी। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में इस्माइल दरबार ने बताया है कि कुछ दिनों पहले ही जैद ने अपनी मां (आएशा) को फोन करके के बारे में बताया है। उन्होंने कहा की जैद, गौहर की बहुत तारीफ कर रहा था और उसने अपने रिश्ते के बारे में भी बताया। आगे जब उनसे पूछा गया कि क्या गौहर को उनका आशीर्वाद मिलेगा तो इसपर इस्माइल ने कहा, अगर जैद और गौहर शादी करते हैं तो मैं क्यों उसे आशीर्वाद नहीं दूंगा। अगर जैद उससे शादी करना चाहता है तो मुझे क्या एतराज होगा। वो 29 साल का है और उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। और यही मेरी पत्नी आएशा ने भी उससे कहा कि अगर वो खुश है, तो हम भी खुश हैं और वो इतना बड़ा है कि उसे पता है उसके लिए क्या सही है। आगे इस्माइल ने बताया, मुझे फेक बनना पसंद नहीं है। सीधी बात है मैंने भी दूसरी शादी की है और मेरे पहली पत्नी (फरजाना, जैद की मां) से रिश्ते ठीक नहीं थे। अगर हम ठीक होते तो मुझे दोबारा शादी नहीं करनी पड़ती। बच्चों ने कभी मेरी पर्सनल जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं किया। मेरे पहली पत्नी से चार और दूसरी पत्नी से एक बच्चा है। मैं अपने बच्चों से बेहद करीब हूं। गौहर खान और जैद कुछ दिनों से लगातार साथ डांस वीडियो और कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही एक्ट्रेस ने अपना जन्मदिन मनाया है जिसमें दोनों ने एक जैसे कपड़ों में कपल गोल्स सेट कर रहे हैं। इससे पहले गौहर खान कुशल टंडन को डेट कर चुकी हैं।

14 शुरू होने से पहले सामने आए ये कड़े नियम

टीवी के सबसे फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 14 जल्द ही शुरू होने वाला है. शो का ग्रैंड प्रीमियर 3 अक्टूबर को होगा. सलमान खान एक बार फिर शो को होस्ट करेंगे और एंटरटेनमेंट का डोज बढ़ाएंगे. इसी बीच बिग बॉस 14 को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, शो के शुरू होने से पहले ही बिग बॉस हाउस के नियमों का खुलासा हो गया है. घर में रहते हुए कंटेस्टेंट को इन सभी नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. बिग बॉस के घर में लागू होने वाले इन नियमों का खुलासा ट्रेंडज्ञान के इंस्टाग्राम द्वारा किया गया है.

बिग बॉस के घर के नियम कोरोनावायरस को देखते हुए बनाए गए हैं. जिसके अनुसार, कंटेस्टेंट्स को डब्ल बेड नहीं दिए जाएंगे और ना ही वह किसी के साथ बेड शेयर करेंगे. खाने की प्लेट और ग्लास कोई भी किसी का इस्तेमाल नहीं करेगा. शुरुआती हफ्तों में कोई भी फिजिकल टास्क नहीं होगा, जिसमें कंटेस्टेंट एक दूसरे को छू सकते हैं. कंटेस्टेंट्स का हर हफ्ते कोविड 19 टेस्ट होगा. इसके अलावा, बिग बॉस के घर में मिनी थियेटर, मॉल, रेस्टोरेंट कॉर्नर और स्पॉ भी मौजूद होगा. सलमान खान के शो में इस बार खबर है कि नैना सिंह, जैस्मीन भसीन, करण पटेल, निशांत मलकानी, एजाज खान, राहुल वैद्य, सारा गुरपाल, शगुन पांडे, प्रतीक सेजलपाल और जान कुमार सानू बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें भी सामने आ रही हैं कि बिग बॉस 14 में सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, गौहर खान, मोनालिसा और शहनाज गिल करीब दो हफ्ते घर के अंदर रहेंगे और घर के सभी काम में हिस्सा भी लेंगे. माना जा रहा है कि इस साल शो की थीम जंगल पर आधारित होगी, जो लॉकडाउन की स्थिति से इंस्पायर होगी.

राहिल को अंकल सैम कहकर बुलाते हैं इंडस्ट्री के लोग

सुशांत केस में ड्रग्स एंगल को लेकर जांच शुरू करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) का शिकंजा अब बॉलीवुड पर भी कसता का रहा है। ड्रग्स मामले में कार्रवाई करते हुए एनसीबी ने कुछ दिन पहले ड्रग सप्लायर राहिल विश्राम राफत को पकड़ा है। अब इससे पूछताछ में कई बॉलीवुड के कई बड़े नामों का खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो एनसीबी जल्द बॉलीवुड से जुड़े इन लोगों से पूछताछ कर सकती है। राहिल फिलहाल सोमवार तक एनसीबी की कस्टडी में है। बॉस नाम के शख्स के लिए काम करता है राहिल जांच में सामने आया है कि ड्रग्स की दुनिया में राहिल को सैम अंकल के नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहिल बॉस नाम के शख्स के लिए काम करता है। बॉलीवुड से जुड़ा बॉस कोई एक्टर या कोई डायरेक्टर या फिर कोई प्रॉड्यूसर हो सकता है। एनसीबी अगर उस तक पहुंचने में कामयाब रही तो कई बड़े चेहरों पर शिकंजा कास सकता है।

कंचन उजाला
हिंदी दैनिक

स्वामी नमोकंचन कार्पोरेट सर्विसेस (एल.एल.पी) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक कंचन सोलंकी द्वारा उमाकान्ती ऑफसेट प्रेस, ग्राम डेहवा पोस्ट मोहनलाल गंज लखनऊ से मुद्रित एवं 61/18 चुटकी भण्डार हुसैनगंज लखनऊ से प्रकाशित।

संपादक- कंचन सोलंकी

TITLE CODE- UPHIN48974

Mob: 8896925119, 9695670357
Email: kanchansolanki397@gmail.com

नोटः समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारो एवं लेखों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नही। समस्त विवादो का निस्तारण लखनऊ न्यायालय के अधीन होगा।